(viii) DHARNA IN DELHI BY COLLEGE AND UNIVERSITY TEACHERS IN ORDER TO PRESS THEIR DEMANDS

PROF. RUP CHAND PAL (Hooghly) : Sir, hundreds of college and university teachers under the banner of All India Federation of University and College Teachers Organisations are sitting in a 'Dharma' at Delhi today (19.4.82) to press their 12 point charter of demands. Their demands include statutory provisions or service security, abolition of private management of colleges, revision of pay scales and single running grade for all teachers including teachers of minority run colleges and full neutralisation of erosion of real wages as a result of direct payment from treasury, implementation of pay scales of Demonstrators. Librarians, Physical Instructors, Tutors, Assistant Teachers, Cartographers, etc., immediate Central approval to the West Bengal Bills for taking over of 3 colleges, representation of the Federation of College and University Teachers' Organisations on the University Grants Commission, and on the Central Advisory Board of Education, recognition of the All India Federation of the University and College Teachers' Organisations, democratisation of governance of colleges and universities, full civil and political rights or teachers, abolition of discrimination between teachers of State and Central Universities and Colleges affiliated to them in respect of all perquisites. common cadre for Class II and Class III Teachers and age of superannuation not below 60 years.

The College and University Teachers would demonstrate at Boat Club Maidan and wait on a deputation to the Hon. Education Minister to press the above demands.

I urge upon the Central Government to consider and fulfil at an early date the very just demands of the college and university teachers of the country. I hope the hon. Education Minister would make a statement in the House in this regard.

12.24 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS, 1982—82—*Contd*

MINISTRIES OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT— *Contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER : The House will now take up further discussion and voting on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Agriculture. Shri Pius Tirkey was on his legs. The time allotted for the entire discussion was about 10 hours. We have already exhausted 7 hours and 41 minutes. The balance of time is about 2 hours and 19 minutes. The hon. Minister will reply round-about 2-30 P.M. Now, Shri Pius Tirkey may continue his speech.

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुर द्वार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि कृषि संबंधी शिक्षा ब्लाक लेबल पर उपलब्ध कराई जानी चाहिये। अभी तक जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वे शहरों में बनाये गये हैं, वहां से शिक्षा प्राप्त लोग गांवों में आना पसन्द नहीं करते हैं।

इसी प्रकार बिजली इत्यादि आधुनिक उपभोग की वस्तुएं भी शीघ्र से शीघ्र देहातों तक पहुंचाई जानी चाहिये, इससे कृषि उपज को भी बढ़ावा मिलेगा।

लैंड रेफार्म की बात जिस दिन से आजादी प्राप्त हुई है, उस दिन से कही जा रही है, लेकिन इसमें अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हुई है। यह बहुत ताज्जुब की बात है कि ऐसे 12 प्रतिशत लोग जो खेती स्वयं नहीं करते हैं, बल्कि मजदूरों या भागदारी के आधार पर करवाते हैं, उनके पास कुल कृषि भूमि का 60 प्रतिशत भाग

*Moved with the recommendation of the President.

[श्री पीयूष तिरकी]

है । किसी के पास तो हजार, दो हजार, चार हजार एकड़ तक जमीन है । यह एक तरह का नया शोषक वर्ग पैदा हो रहा है जो गरीब का शोषण कर रहा है और उनको उचित मजदूरी भी नहीं दे रहा है । इसलिये मेरा अनुरोध है कि लैंड रेफार्म की तरफ सरकार को बहुत ध्यान देना चाहिये और जिन लोगों के पास अधिक भूमि है, उनसे लेकर समितियों को दे देनी चाहिये, ताकि ग्रामीण अंचल के लोगों को ज्यादा सुविधा मिल सके और उनमें उत्साह बढ़े कि वे स्वयं अपने जीवन निर्वाह के लिये उत्पादन कर रहे हैं ।

कुछ कृषक तो ऐसे हैं जिनके पास .5 एकड़ से भी कम जमीन है । ये कृषक आधुनिक उपकरणों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं । ये लोग महाजनों के ऋण से दबते जा रहे हैं । गांवों में भी पूंजीवादी व्यवस्था स्थापित हो रही है । इन किसानों की जमीन लीज पर ली जा रही है । जिस किसान के पास एक एकड़ जमीन है और वह 5.10 मन अनाज पैदा करता है, उसको कहा जाता है, कि तुम अपनी जमीन हम को दे दो हम तुम्हें इससे ज्यादा अनाज देंगे, इस तरह से छोटे किसानों की जमीनें हड़पने की कोशिश की जा रही है । इस ओर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है

हम इतना अनाज उपजाते हैं, इतना अनाज हमारे पास होने के बावजूद 51 प्रतिशत से अधिक लोग गरीबी की सीमा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं । हम समझते हैं कि जिस आदमी के पास खाने-पीने की व्यवस्था नहीं है, वही गरीबी की सीमा से नीचे हैं । इतनी उपज होते हुये हम उन लोगों को अनाज नहीं दे पा रहे हैं ? हमारा अनाज गोदामों में सड़ जाता है, लेकिन गरीब आदमी को पेट भरने के लिये अनाज नहीं दे पा रहे हैं । इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये । बहुत से लोग बिना खाये रह रहे हैं । इससे बच्चों में बहुत सी बीमारियां हो रही हैं । इसलिये सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये :

कॉटेज इंडस्ट्री की बात बहुत की जाती है । इस महत्व को भी बताया जाता है । देहातों में जहां जहां पर खेत हैं वहां साथ साथ जंगल भी हैं । आजकल होता यह है कि जंगल की लकड़ी जलावन के व्यवहार में लाई जा रही है । इसको बचाया जाना चाहिये और फारेस्ट बेस्ड कॉटेज इंडस्ट्रीज वहाँ पर लगाई जानी चाहिये । ब्लाक लेबल पर छोटी और स्माल स्केल इंडस्ट्री के लिये वहां लोगों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जानी चाहिये । कृषि के काम से जब उनको फुर्सत मिलती है तो वे शहरों की तरफ काम धंधा ढूंढने के लिये भागते हैं । उनको वहां जाना न पड़े और आसपास ही उनके कॉटेज इंडस्ट्रीज में उनको काम मिल जाय और पैसा भी मिल जाय तो वे शहरों की तरफ नहीं जायेंगे और उनको वहीं काम मिल जाएगा ।

जिन कर्मचारियों को ग्रामीण विकास के काम करने के लिये, ग्रामीणों में काम करने के लिये भेजा जाता है, आपको यह भी देखना चाहिये कि क्या उनका ग्रामों की उन्नति करने की ओर झुकाव है भी या नहीं ? यह पहला उनका टैस्ट होना चाहिये। आपको यह भी देखना चाहिये कि जिस इलाके में उनको भेजा जा रहा है उस इलाके की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था का उनको कुछ ज्ञान है या नहीं, आदिवासियों के रहन-सहन से वे परिचित है या नहीं । यह बहुत जरूरी है। आज कहने को तो काम बहुत हो रहा है लेकिन सब कागज पत्रों में ही हो रहा है । वास्तव में ग्रामीण इलाकों की भलाई हो, उनकी उन्नति हो इस तरफ भी ध्यान देना बहुत जरूरी है ।

श्री मलिक एम० एम० ए० खां(एटा) : सबसे पहले में दरख्वास्त करूंग कृषि मंत्री जी से कि उन्होंने जो 142 रुपये गेहूं की कीमत मुकर्रर की है, बहुत हल्के लफ्जों में मैं कहूंगा तो यह कहूंगा कि किसान के साथ उन्होंने इंसाफ नहीं किया है। पिछले साल 130 रुपये कीमत थी, आज 142 है। लेकिन फर्टिलाइजर की कीमत आपने 17 परसेंट बढ़ा दी है, डीजल की 40 परसेंट। बिजली पूरे पैसे लेने के बाद भी किसान को मिले या न मिले इससे सरकार का कुछ ताल्लुक नहीं। इनपुटस की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। पूरा कैलकुलेशन करूंगा तो बहुत समय लग जायगा। लेकिन मेरे हिसाब से आपने जो 142 रुपये दिये हैं उसमें से 22 रुपये आप वापिस ले लेते हैं बढ़ी हुई फर्टिलाइजर की कीमत के रूप में, डीजल की बढ़ी हुई कीमत के रूप में वगैरह वगैरह। सही मानों में आपने उसको 120 रुपये दिये हैं 142 नहीं। आम एवरेज लगाते हैं पैदावार का। आप कहते हैं कि एक एकड़ में दस क्विंटल पैदा होता है हालांकि होता नहीं है। दस क्विंटल एवरेज हर किसान के यहां पैदा नहीं होता है। लेकिन इसी एवरेज पर अगर आप हिसाब लगायें तो 142 रुपये में से 22 रुपये आप वापिस ले लेते हैं।

ए पी सी क्या बीमारी है? उनमें कोई है ऐसा जो किसान से हमदर्दी रखता हो, किसान की प्राबलैम्ज को, उसके मसाइल को समझता हो, किसान जो मेहनत खेत पर करता है, उसका अन्दाजा लगा सकता हो। किसान के साथ वह हर्गिज इंसाफ नहीं हुआ है। वह मार्किट में जाता है तो साठ रुपये में उसको सिमेंट की बोरी मिलती है, 5–6 रुपये किलो चीनी मिलती है। सभी जरूरियातें जिन्दगी की चीजों की उसको ज्यादा कीमत देनी पड़ती है। वह खून पसीना बहा कर गेहूं पैदा करता है, दूसरी खेती की चीजें पैदा करता है। ए पी सी उसकी पैदावार की कीमतें दिल्ली में एयर कंडिशंड कमरों में बैठकर तय करती है, यहां पर उसके द्वारा पैदा की गई चीजों की कीमतों का फैसला होता है। यह भी उस देश में जिस देश में अस्सी परसेंट किसान रहते हैं, जो देश किसान की पैदावार पर निर्भर करता है, जो खून पसीना बहाकर हमको पैदा करके देता है। तो मेरा निवेदन है कि 142 रु० आप देंगे लेकिन कम से कम जो हिसाब मैंने बताया है मैं चाहूंगा उसका आप कैलकुलेशन कर लें और बतायें कि क्या यह सही नहीं है कि उसमें से 22 रु० आप इन कीमतों की वजह से वापस ले लेते हैं? मैं जिस कांस्टीट्यूऐंसी से आता हूं हजारों एकड़ वहां ऊसर है। 32 साल आजादी के हो गये, आपकी आई० सी० ए०आर० है, मुल्क में आबादी बढ़ रही है, जमीन की जरूरत है, मैं जानना चाहता हूं कि आपने ऊसर को रिकलेम करने के बारे में कोई काम किया है या नहीं। ऐटा जिले में आज तक सरकार ने 5 एकड़ ऊसर रिक्लेम नहीं किया है। जब कि प्राइवेट सैक्टर के हिन्दुस्तान लीवर ने कम से कम 100 एकड़ आवागढ़ क्षेत्र में, जहां खार जमीन थी और खाक नहीं होती थी, एक कैमिकल तैयार करके कमर कमर तक गेहूं पैदा कर रहे हैं। इन्होंने एक सोल्यूशन तैयार किया है हिन्दुस्तान लीवर ने, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, अगर उसको फसल पर स्प्रे कर दें तो 35 परसेंट यील्ड बढ़ जायगी। और वह सोल्यूशन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, हिसार से मिल कर उन्होंने बनाया है। और हमारी कांस्टीटयूऐंसी में तजुर्बा किया है कि फसल खड़ी होने के मैं बाद अगर स्प्रे कर दिया जाये तो गेहूं मोटा हो जाता है, यील्ड 35 परसेंट बढ़ जाती है। आज पैदावार बढ़ाने की जरूरत है और जब आपके यहां एप्लाई कोई करता

[श्री मलिक एम० एम० ए० खां]

है तो पहले तो आई सी० ए आर० के तौर तरीकों से गुजरे तब आप उसको सैंक्शन देंगे। आप ही यूनिवर्सिटी से मिल कर उन्होंने यह सोल्यूशन तैयार किया है। फिर आप रेड टेपिज्म को क्यों बढ़ा रहे हैं? अगर आई० सी० ए० आर० को करना है तो जल्दी से कर लें ताकि दूसरे साल वह पोपुलराइज हो और 35 परसेंट यील्ड में बढ़ोत्तरी मिल सके।

अभी अखबार में पढ़ा है, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि आयल रिसोर्सेज हमारे पास होते हुये भी हम हजारो रु० का आयल इम्पोर्ट करते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि फूड कारपोरेशन ने एक कमेटी मुकर्रर की थी जिसकी रिपोर्ट है कि राइस ब्रान जो होता है जिसको पंजाब में गधे और घोड़े खा जाते हैं, उसमें 25 परसेंट ऐडिबिल आयल होता है। राइस ब्रान आयल कमेटी की रिपोर्ट है जो माडर्न राइस मिल्स हैं उनके साइड बाई साईड एक्सट्रेक्शन प्लान्ट लगाये जाय और राइस ब्रान से आयल निकाला जाय तो आपको एक पैसे का भी ऐडिबिल आयल इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर आपकी समझ में नहीं आता। मंत्री जी को जरा फुर्सत कम होती है, नीचे से जैसा नोट आया उसी पर दस्तखत करके वापस कर देते हैं। पिछली दफा मैंने कहा था कि आपकी अन्डरटेकिंग्स का बुरा हाल है। एफ० सी० आई० का मैं जिक्र कर चुका हूं, एक आपकी एन० बी० आई० अन्डरटेकिंग है। मैं फूड कारपोरेशन का डायेक्टर था जब मेज प्लान्ट लगाने की बात चली, मैंने विरोध किया कि फरीदाबाद में काम नहीं होगा। श्री इकबाल सिंह उस वक्त चैयरमैन थे....

मैंने उसी वक्त एप्रोच किया कि यह कामयाब नहीं होगा इत्तिफाक से उस वक्त जो फूड कारपोरेशन के चेयरमैन थे वह सैक्रेटरी हो गये, आई० ए० एस० थे। लिहाजा उज्जैन आयल प्लान्ट, जो सवा दो करोड़ रुपये का नुकसान एफ० सी० आई० को दे चुका था, और मेज प्लान जो बराबर नुक्सान दे रहा था, वह इन आई०ए-एस० साहब ने, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ने सैक्रेटरी साहब के साथ मिलकर फूड कारपोरेशन जैसे हाथी से निकालकर इस गरीब ए० बी० आई० जो जरा अच्छे ढंग से चल रही थी, उसके सुपुर्द कर दिया और 36 लाख रुपये कास्ट मुकर्रर की गई। पहली साल में उसमें 28 लाख रुपये का नुक्सान हुआ और इस साल 32 लाख का नुक्सान हुआ। इस तरह से 60 लाख 66 हजार एम० बी० आई० नुक्सान दे चुका है 36 लाख की प्लांट में। मंत्री जी को फुरसत नहीं है यह देखने की कि कहां बरबादी हो रही है।

5 लाख रुपये साल मेज प्लान्ट नुक्सान दे रहा है जो कि आपने माडर्न बैकरीज को दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि इसे माडर्न बैकरीज को क्या दिया? एफ० सी० आई० बहुत बड़ा आर्गेनाइजेशन था, जिसको 26 करोड़ रुपये सबसीडी आप देते हैं। उसको 100 करोड़ दे देते। एम बी० आई० को बरबाद करने के लिये यह आपने उसे क्यों दिया जब कि आप जानते थे कि सवा 2 करोड़ का नुक्सान हो रहा है। वही सैक्रेटरी कंबिनेट सैक्रेटरी हुये। ऐसे लोगों की तरक्की होती है। मैं पूछना चाहता हूं कि सवा दो करोड़ रुपये जिसमें नुक्सान हो रहा था, वह आपने इस छोटी सी अन्डरटेकिंग में क्या दिया। मुझे तकलीफ इस लिये हो रही है कि मैं उसका चार साल तक चेयरमैन रहा हूं।

जब मैंने 1971 में चार्ज लिया तो इसमें 68 लाख का नुक्सान था। जितनी अन्डरटेकिंग्ज आपकी गवर्नमेंट आफ इंडिया की है, ऐस मालूम होता है कि यह आपने

बनाई ही नुक्सान के लिये हैं। पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिव जो होता है, उसको अक्ल नहीं होती । मैं एम० बी० आई० की मिसाल से साबित करुगा कि इसको बनाने वाला पब्लिक रिप्रेज़ेन्टेटिव था और बरबाद करने वाला आई० ए० एस० था ।

68 लाख के लास में मुझे यह मिली थी जब मैंने इसका चार्ज लिया । उसके पहले आई० ए० एस० वहां पर थे । पहले साल में 71–72 में ही 54 लाख का प्राफिट हुआ और 1972–73 में 62 लाख का प्राफिट हुआ और 1973–74 में भी 62 लाख का प्राफिट हुआ ? और 1974–75 में एक करोड़ 3 लाख का प्राफिट हुआ और उसमें भी 3 लाख रुपया आउट स्टैंडिग था । इस तरह से आउट स्टैंडिंग का मिला कर 1 करोड़ 6 लाख का प्राफिट हुआ, जब मैंने इसको छोड़ा था । जब कि मैं रिटायर हो गया, उसमें फिर आई ए एस तशरीफ लाये । 1975–76 में इसमें सिर्फ 77 लाख का प्राफिट रह गया और चार्ज यह लगाया कि चूंकि 10 जुलाई 75 को चेयरमैंन ने 10 पैसे ब्रैंड की क़ीमत कम कर दी थी, इसलिये प्राफिट कम हो गया ।

जगलरी में ये लोग माहिर होते हैं, फाइल को उलट पलट करने में, कागज को इधर से उधर करने में । हमारे मिनिस्टर साहब ने तो दस्तखत मार दिये और कागज को भेज दिया । यह नहीं देखा किसी ने कि जिस वक्त 10 पैसे कम किये गये थे, तो रा-मैटीरियल की क़ीमत साढ़े 7 पैसे उस वक्त कम हो चुकी थी जो कि मैंदे और दूसरी चीजों की क़ीमत थी । और ढाई पैसे मैंने मीटिंग करके इकनामी के आधार पर कम किया, ताकि प्राफिट बरकरार रहे । मैंने एक प्रोफार्मा जारी रखा था, जो आज भी एम० बी० आई० के रिकार्ड में मौजूद है जो हर यूनिट में मौजूद है जिसमें जुलाई से लेकर नवम्बर तक 18 लाख रुपये प्राफिट के बचे थे ।

कहते हैं कि छः महीने में प्राफ़िट घट कर 17 लाख रुपये इस लिए रह गया कि ब्रेड की क़ीमत में दस पैसे कम किए थे दस पैसे इस लिए कम किए गए थे क रा मैटीरियल की क़ीमत कम हो गई थी ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have rung the bell to tell you that you have already exhausted 15 minutes. You may continue. I have not stopped you.

श्री मलिक एम एम ए खां : मैं तो अभी दस मिनट बोला । हू यह तो इण्ट्रोडक्शन है । अभी तो मैंने शुरू नहीं किया है ।

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur) : He rung the bell to appreciate your speech.

श्री मलिक एम० एम० ए० खां : मैं सही बात कह रहा हूं । किसी के पसंद करने या नापसन्द करने से ज्यादा ताल्लुक नहीं है । में अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूं ।

मैं इस बारे में आंकड़े देना चाहूंगा । एम बी आई को 1.6 करोड़ रुपये का प्राफ़िट हुआ था, लेकिन जब आई ए एस साहब तशरीफ लाए तो 1975–76 में वह घटकर 17 लाख रह गया । उसके बाद 1976–77 में 43 लाख रुपए, 1977–78 में 57 लाख रुपये, 1978–79 में 46 लाख रुपये, 1979–80 में 49 लाख रुपये और 1980–81 में 45 लाख रुपये का प्राफिट हुआ । जब 16 करोड़ रुपये का प्राफिट हुआ, तो 11 लाइनें थीं । उसके बाद एक्सपेंशन हुआ और 7 लाइनें और बढ़ा दी गई । इसका मतलब यह है कि इनके वक्त में जो प्राफिट हुआ वह 18 लइनो पर हुआ ।

[श्री मलिक एम० एम० ए० खां]

उसके बाद एक एक्स-एम पी जुलाई में एम बी आई के चेयरमैन मुकर्रर हुए और उसके बाद प्राफिट हुआ 1.70 करोड़ रुपए । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हू कि यह जादू कैसे हुआ कि एक ही साल में प्राफ़िट 45 लाख रुपये से बढ़ कर 1.70 करोड़ रुपये हो गया । यह रुपया कहां जाता था ? यह जनता के खून-पसीने का पैसा है ।

जब मैंने इस कम्पनी का चार्ज लिया था, तो इसके एसेट्स 2.13 करोड़ रुपये के थे । नवम्बर, 1975 में जब मैंने चार्ज छोड़ा, तो 1.6 करोड़ रुपये के प्राफ़िट के अलावा 8 करोड़ रुपये के ऐसेट्स छोड़े । मैं कहना चाहता हूं कि अगर सरकार पब्लिक अण्डरटेकिंग्ज़ को सम्भालने में दिलचस्पी रखती हो, तो उन्हें संभाला जा सकता है ।

मुझे गौरव है इस बात का कि मैं सब से पहला आदमी हूं, जिसने एम0 वी0 आई में वर्क़र्ज़ को 20 परसेंट बोनस दिया । जब मेरे बुजुर्ग, जिनकी मैं बड़ी इज्ज़त करता हूं, और श्री जार्ज फर्नाण्डीस रेलवे के वर्क़र्ज़ के लिए लड़ रहे थे, तो वे एम बी आई को मिसाल देते थे कि वहां के क्लास फोर के लोगों को जो बोनस मिलता है, वह रेलवे में भी मिलना चाहिए । मैंने मद्रास में इस तरह के पोस्टर देखे । मैंने क्लास फ़ोर के वर्क़र्ज़ को 600, 650 रुपये की सैलेरी दिलाई और टेरीकोट की वर्दी पहनाई । लेकिन आई ए एस साहब ने वह टेरीकाट की वर्दी छीन ली । उनका कहना था कि क्या स्वीपर को भी टेरीकोट की वर्दी पहनने का अधिकार है ।

मेरा दावा है कि प्राईवेट सैक्टर कभी भी पॉब्लिक सैक्टर का मुकाबला नहीं कर सकता । ब्रिटेनिया एक मल्टी नेशनल कंपनी है । वहां पर स्ट्राइक हुई, तो उसके वर्क़र्ज़ ने मांग की कि एम बी आई के वर्क़र्ज़ को जो सैलेरीज और वेजिज़ मिलते हैं, वे हमें मिलने चाहिए । ब्रिटेनिया ने अपनी ब्रेड की कीमत बढ़ाने के लिए लेफ्टिनेंट-गवर्नर को प्रोपोज़ल दिया । लेफ्टिनेन्ट गवर्नर ने प्रोपोज़ किया कि 30 पैसे कीमत बढ़ा दी जाए और ब्रेड की कीमत ढाई रुपये कर दी जाए । इसके मुकाबले में पब्लिक अण्डरटेकिंग के चेयरमैन एक्स-एम पी ने लिख कर दिया कि मौजुदा क़ीमत पर ही हम 1.70 करोड़ रुपये का प्राफिट कर सकते हैं । एम बी आई में आज भी वर्क़र्ज़ को 20 परसेंट बोनस दिया जाता है । मैं हैड आफ़िस के वर्क़र्ज़ को भी 20 परसेंट बोनस देता था । पर आज हेड आफिस के वर्क़र को 20 परसेंट बोनस न मिल रहा है जिसका मुझे दुख है और आप देखिए, कोई देख रहा है ? कोई देखने वाला नहीं है । वही लीगल ऐडवाइज़र जो मेरे ज़माने में लीगल ऐडवाइस देता है कि हेड आफिस में 20 परसेंट बोनस दिया जा सकता है, वही लीगल एडवाइज़र है, जब मैं चला आया, उस से लीगल ऐडवाइस मांगी गई तो उस से मैनेजिंग डाइरेक्टर ने लिखवा लिया कि 20 परसेंट बोनस नहीं दिया जा सकता, 8.3 परसेंट दिया जा सकता है । वह अभी भी वहां है । देख लीजिए फाइल मंगा कर । मिनिस्टर साहब कोई नोट कर रहे हैं या कोई है ही नहीं नोट करने वाला ? वही लीगल ऐडवाइज़र मेरे ज़माने में यह ऐडवाइस देता है कि हेड आफ़िस के वर्क़र को 20 परसेंट बोनस दिया जा सकता है, मेरे चले आने के बाद मैनेजिंग डायरेक्टर ने उस से लिखवा लिया कि 8.3 परसेंट दिया जा सकता है । लिहाज़ा एक ही कम्पनी का एक वर्क़र 20 परसेंट बोनस ले, दूसरा 8.3

परसेंट, यह हो रहा है । क्यों उन के साथ इस किस्म की नाइंसाफियां फरमा रहे हैं ?

मुझे माफ करेंगे मेरे बुजुर्ग दोस्त, ऐसी बढ़िया कम्पनी जो डिविडेंड दे, 20 परसेंट बोनस दे, एक्सपेंशन जिस का हो रहा था, जनता पार्टी ने इस को स्माल स्केल इडस्ट्री में डाल दिया । हमारे चौधरी साहब इस के कुछ खिलाफ थे, ऐसा मैंने सुना है । वह चाहते थे कि इस को स्टेट दिया जाय । लिहाजा इस को स्माल स्केल इडस्ट्री डिक्लेयर कर दिया । सारा डेवलपमेंट रुक गया । इसका एक्सपेंशन प्रोग्राम सारा रुक गया । मैं निवेदन करूंगा मिनिस्टर साहब से, जरा नोट कर लें, जनता पार्टी के इस आर्डर को रिवाइज करवा दें जिस से कि जो एक्सपेंशन है वह जारी रहे ।

मैं जब आया तो इस का रेंपिग पेपर करोड़ों रुपए का खरीदा जाता था । मैं प्रोजेक्ट तैयार कर के आया कि इस का प्रोजेक्ट लगा दिया जाय । उससे और प्राफिट बढ़ जाता । जो मिडिल मैन का प्राफिट है, वह अगर अपनी फैक्ट्री लग जाती, अपनी मशीनरी हो जाती वह हम को मिलता । इसी तरह यीस्ट की मोनोपली है एक कम्पनी की । ये सब सांठ गांठ किए रहते हैं । मैंने प्रोजेक्ट बनाया था .... (व्यवधान) .. मैं यह है न राज ? वही तो राज मैं चाहता हूं, मेरी ड्यूटी है कि मैं खोल दूं । यीस्ट की मोनोपली एक कम्पनी है । यीस्ट का प्रोजेक्ट बना हुआ तैयार है कम्पनी में । अगर थे दो साल और रहा होता तो दोनों फैक्ट्रियां ले आता । ईस्ट का भी प्रोजेक्ट बना हुआ रखा है; रपिंग पेपर का प्रोजेक्ट बना हुआ रखा है ।

इसी तरह नान के बारे में दिल्ली के बहुत से लोगों को याद होगा । मैंने नान तैयार कराया इसलिए कि जो आफिस जाने वाले हैं उनको ईज़ी फूड मिल जाय जल्दी से । सिर्फ एक रुपये का एक पैकेट मिलता था । कैण्टीन्स के अन्दर एक रुपये का एक था । तीन दिन तक खा सकते थे । अंगीठी पर गरम किया और फ्रैश हो जाता था, चार आने की सब्जी ले कर खा सकते थे । वह नान का प्लाण्ट भी बेच दिया । हमारे आई ए एस के आफिसर साहब ने नान बनाना तो दूर रहा । मैंने नान बना कर बेचे भी । उन्होंने नान का प्लाण्ट ही बेच दिया । मैंने पी-नट बटर भी तैयार किया । उन्होंने पी-नट बटर का भी फन्दा काट दिया । मैं जानता हूं आप के पास फुर्सत कम है, मगर जरा देखिए तो सही कि यह हो क्या रहा है ? आप शायद थर्ड, मन्थली रिव्यु करते हैं ? क्या रिव्यू करते हैं ? ये मुख्य चीजें हैं जिस में कि भारी नुकसान है ।

मेरी राय है कि अगर पब्लिक अण्डरटेकिंग्स को मजबूत करना है, उनको बढ़ावा देना है, सही लाइन पर लाना है तो आफिशियल और नान-आफिशियल में आप काम्पीटीशन क्रिएट कीजिए । दो कम्पनियों में आप के चेयरमैन हैं। मेरा कहना है कि चैयरमैन को पावर्स मुकर्रर कीजिए ताकि आपस में काम्पीटीशन हो । यह मेरा प्रोपोज़ल है । यह केवल आई ए एस या दूसरे आफिसर ही जो हैं उन की यह जागीर नहीं है । जो पब्लिक के भेजे हुए लोग हैं वह भी यह काम कर सकते हैं और ईमानदारी से, मेहनत कर सकते हैं । इसीलिए मैंने एम बी आई को मिसाल दी । मैं दो मिनट और लूंगा ।

[श्री मल्लिक एम० एस० ए० खां]

मैं दो मिनट में खत्म कर रहा हूं । मैं बेकार बात नहीं कहता । (व्यवधान) मैं चाहता हूं कि जो पब्लिक सेक्टर है उसमें सिर्फ उसी ही जागीर न बने बल्कि मुल्क के अन्दर जो और रोग हैं जो कि सेवा कर सकते हैं उनको भी मौका मिले । दूसरी बात यह है कि कुछ ऊपर के जो ऐसे चेयरमैन होते हैं विदाउट हैण्ड्स ऐण्ड लेग्ज़ उनको रखने से क्या बात हुई ? आप चेयरमैन तो मुकर्रर करें लेकिन उसके हाथ-पैर काट दें तो क्या फायदा होगा ? एम बी आई में यह हो रहा है । चेयरमैन कोई आर्डर भेजता है तो मैनेजिंग डायरेक्टर कहता है इसको फेंक दो । मैं यह जानना चाहूंगा कि एम बी आई में चेयरमैन ने कितने आर्डर दिए और उसमें से कितने इम्प्लीमेण्ट हुए ? वहां पर चेयरमैन कुछ लिखता है तो मनेजिंग डायरेक्टर उसको उठा कर रद्दी की टोकरी में फेंक देता है । इसलिए अगर आप कोई चेयरमैन मुकर्रर करते हैं तो उसके हाथ-पैर काटकर नहीं हाथ-पैर जोड़ कर मुकर्रर कीजिए । मैं यहां पर किसी की कोई बुराई नहीं करना चाहता । मैं तो चाहता हूं कि कांपिटीशन क्रिएट हो ताकि मालूम हो सके कि वह भी कुछ काम कर सकते हैं या नहीं ।

आखिर में मैं आपका बहुत मशकूर हूं कि आपने मुझे काफी टाइम दिया । शुक्रिए के साथ ही थे अपनी बात खत्म करता हूं ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Dhandapani. Your party has been allotted 16 minutes.

SHRI C. T. DHANDAPANI (Pollachi): Sir, we are discussing the Report of the Ministry of Agriculture, which contains the figures supplied by the various States. So far as the compilation of the figures supplied by the State Governments concerned, I have my own doubts whether they are authentic or not, because the hon. Minister of Agriculture, Rao Birendra Singh, stated once in a function that the claims of food production by the States are exaggerated. So, there may be some exaggeration in the figures given by the states to the Centre. I do not know whether the figures supplied by the States are correct or not. I thought I should mention this when I deal with the Report.

It is well-known that agriculture is a State subject. The Centre can only evolve some policy and give direction to the States. At the same time, the Centre has no monitoring institution to have a check over the performance of the States with regard to the policies which have been evolved and passed on to States. Though there are periodic discussions with the State Ministers, the performance is very poor in many States.

So far as self-reliance is concerned, it is stated that in 1966 we imported foodgrains to the extent of 103 lakh tonnes. Now we are in a position to export foodgrains to other countries for which the entire country and the Parliament are indebted to the farmer community. But what is the position of the farmers today? Their debt is increasing day by day. The farmers are becoming actually paupers. The Government should think over it and find out some other way because Agriculture is not a service, it is an industry which can create more employment Not only that. This is a basic industry which is responsible for other financial activities of the country. Even in the statement, it is stated, and I would quote:

"Agriculture contributes about 40 per cent of the Gross National Product, more than 60 per cent of the exports and 70 per cent of the working population of the country

are dependent on agriculture which can justifiably be called the Mother of Indian Economy."

13 hrs.

So, this Mother of Indian Economy is, according to Rao Birendra Singh, not self-paying as he stated when he inaugurated the Indian Society of Agriculture Statistics. I would like to quote him here. He said:

> "Agriculture in India has not yet reached a self-paying and self-supporting state".

So, all these days they have not cared for our Mother. What I would request the Government is to take proper steps because all these days we have been discussing and we have been talking on the platform that agriculture is the backbone of our economy and so, we must protect it. We discussed all this. But what is the tangible result? I do not think any improvement has been made in this regard, as expected. I do not say that nothing has been done. It has been done to some extent, but not up to expectation. Therefore, I would request the Government to take some sort of drastic action and tt would be better to have a new look at this aspect.

As far as the other matter, that is, the pricing policy, is concerned, all Members have talked about it stating that they are not at all getting proper remunerative prices for agricultural products. The prices of inputs have gone to the extent of more than 128 per cent between 1970-71 and 1979-80. For example fertilisers have gone up to 95.4 per cent, the increase in inputs in electricity have gone up by 125.6 per cent, about pesticides they has gone up by 172.2 per cent and inputs on diesel have gone up to 220.8 per cent.

These are the figures representing the increase in inputs, whereas the remunerative price for their product is becoming very less. Of course, the Government has appointed the Agricultural Prices Commission. They adopt some criteria which they announce and which does not reflect or fulfil the aspirations of the farmers. The Agricultural Prices Commission is just sitting in Delhi. Many people complained that no farmers are represented in that Commission. Only some technicians and some others, those who can calculate the figures, are sitting in the Agricultural Prices Commission and they announce some prices. So, what I suggest is that this kind of commissions should be there in each State because the problems vary from State to State. The needs of the farmers also differ from State to State. For example, in my State of Tamil Nadu, our Chief Minister says: "I am ready to give more price to sugar cane as well as to paddy. But the Agricultural Prices Commission stands in my way. That is why I am not in a position to give more price." Our hon. Minister, Shri R. V. Swaminathan knows about it because he comes from our State. Our Chief Minister stated this many times. In this regard may be some other Ministers also are making some such statements. So, in this respect why can't the Central Government take a decision to appoint State level Agricultural Prices Commissions so that they can fulfil demands of local farmers? Many Members have stated this in this House. In my State also —Tamilnadu—even to-day the agriculturists are being arrested. More than 4,000 agriculturists have been arrested. Their properties have been attached. I would like to ask the Minister to give a categorical reply as the Chief Minister, Tamilnadu, stated in the Assembly itself that that was the direction from the Central Government, that is why such an action against the farmers—confiscation of goods and attachment of property—was being taken whether such a direction has been issued to the State Government or not.

The agricultural workers are not getting proper wages as has been fixed by the State Government. Now a days they are like bonded labour. In many areas including my area they are not

[Shri C. T. Dhandapani]

at all getting proper wages which have been announced by the State Government. In this connection I would request the Government to bring central legislation in this regard. Once an agricultural labourer, is always an agricultural labourer—his wife, his children. For years to come they have been agricultural labourers. I would therefore like to request the Government to have a separate welfare Board for the purpose. You can collect some cess for the agricutural labourers so that they can be benefited.

IRDP allots money. Rural Employment Scheme has also been provided. In this regard I put a question too in the morning. Money allotted for the purpose, even in Tamilnadu, has been squandered away. Crores of rupees have been squandered away. I do not know what the Central Government is going to do in this regard. The Planning Commission appointed Sivaraman Commission to look into their backwardness and their condition. Planning Commission wanted Sivaraman Commission to submit the report. Sivaraman Commission appointed another Committee—Madras institute of Development Studies. They met at Dharmapuri and Ramnad districts. Our Minister comes from Ramand the Committee made a survey and gave a report stating that money was misused. Several crores of rupees were misused. In this regard I quote from The Economic Times—

> "That is what was done in the districts of Ramnad and Dharmapuri in Tamil Nadu by the Madras Iistitute of Development Studies. Th finding have been an eye-opener. The identification of the target group has been faulty, with most of the benefits being cornered by the better-off farmers, teachers and government officials. The quality of the gain offer ed has been so poor that workers refused to accept wages in kind.... The report mentions that the indebtedness of the poor villagers has actually increased during the programme. It is time that professional teams of economists and other experts evaluated these rural development programmes before more money goes down the drain".

This is a report which has appeared in the *Economic Times*. The Centre also cautioned the State Governments. The Minister, Rao Birendra Singh has said, "The Centre to take action against the erring States" which appeared in the *Economic Times*, on the 29th March, 1982.

So, according to the report of this institution, the Tamil Nadu Government has done a blunder. They misappropriated the funds earmarked for the rural development. Therefore, I would like to know from the Minister, what action the Government propose to take against the State Government.

Another important matter, I would like to touch to which the Minister has also referred is regarding the distribution price. There are some peculiar things which are happening in Tamil Nadu. The Central Government allowed the flour millers to increase their price on 23rd April, 1981. It is applicable to all the States. But the Tamil Nadu Government wanted to give further increase to the millers for maida and suji. When the millers approached the State Government, the State Government advised the millers to approach the Centre for additional increase in the same year. I think, they might have approached the Minister and the officials concerned. They returned without getting anything from the Centre. Again the State Government recommended the case I should say, it allowed the millers to increase their price for maida and suji by its notification on 5th October, 1981. This was issued before Deepavali so that the millers could make money. I can say and I can prove with all documents that the ruling Party took several lakhs from the millers and allowed the millers to increase their price.

Knowing all these things, I wrote a letter to the concerned official in the Food Department because the Central

Government should give its consent for the enhancement in the price of maida and suji. I wrote to the officer because at that time, the hon. Minister Rao Birendra Singh was not in India. He was out of India. The Secretary also was not here. I wrote a letter to the officer—he might be Joint Secretary or whosoever he might be. I wrote to him that the consent of the Central Government should not be given because the State Government increased the price of maida and suji without prior consent. But I do not know what happened afterwards—whether there was any collusion of the State Government with the officials sitting in the Ministry. Permission was given and the people were looted during the Deepavali season. Therefore, I would request the Minister to look into the matter. This is a serious matter and I am going to collect more details in this regard. This is a serious matter and the Minister should look into the matter as to how the officials had given the permission when the State Government had not obtained prior permission from the Central Government.

I will now come to ICAR. Many people talked about this institution from both sides of the House. Of course, it has done a remarkable work. No doubt, about it. But at the same time, I would like to say that inner politics and groupism is rampant in ICAR. Many promotions and appointments were effected on the basis of caste, community, religion and region. This should be stopped. I know many such cases and I even represented the matter. I would like the Minister to give some more details about a particular case which I discussed with the officials also. Many employees were suppressed. In this connection, I wanted a copy of the letter from Mr. U.N. Rao, who is Joint Secretary to the Government of India. I wanted a particular case about the staff. Mr. Rao wrote a letter to the official stating, with reference to such and such letter, you are not eligible for such and such post. He referred to the matter about a particular person. If he refers a letter to a particular person then the person himself is entitled to know what are the contents of the letter. When I asked Mr. U.N. Rao, what are the contents and a copy of the procedure and rule followed, Mr. Rao says, "I am sorry that the Government procedure to be followed in such cases does not permit copies of such correspondence to be furnished." I wanted to konw what are the difficulties of the Department and what are the contents of the letter. But he refused to give. ICAR being a Central institution, this should be decentralised. Every State must have an institution like this so that there cannot be any discrimination amongst scientists who are coming from different regions. We know, many people committed suicide and many people had left their job from ICAR because of some sort of vested interests which are working in the ICAR.

This institution is getting lot of foreign funds from outside, namely, UNDP, UNESCO and FAO. These are the organisations which are contributing to ICAR. I do not know whether the institution is maintaining its account including all contributions, properly or not. This should be scrutinised by a Parliamentary Committee.

Before I conclude, I would like to mention one important matter about the river waters. We talk about Ganga-Cauvery Link and other projects. But as far as India is concerned we have not tapped our water resources properly. I must say, it is only about 35 per cent of the water resources that has been tapped so far. The rest has not been tapped yet. The Government should think over it and this Ganga-Cauvery Link scheme should be implemented immediately so that the down South and the other drought prone area may get benefit out of this scheme.

Finally, all the rivers should be made as national property. In my area, Coimbatore district in the West flowing rivers that is from Kerala State, the water is being wasted. If it

[Shri C. T. Dhandapani]

is diverted to Coimbatore district, it would become another Tanjore district.

The Government should follow some remedial measures. Those are full utilisation of irrigation facilities and expansion of irrigation facilities to drought prone area. Stable supply of crop inputs to small farmers and marginal farmers should be ensured Plant protection measures should be implemented and subsidies to small farmers made available. Payment of remunerative price to farmers should be ensured immediately, because it is hanging fire for many years. The distribution of lands and area of cultivation to landless poor should be made. These are the urgent matters to be looked into by the Government and I hope the Government would take proper and immediate steps in this matter.

With these words I support the Demands.

श्री तपेश्वर सिंह (विक्रमगंज) : उपाध्यक्ष महोदय मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कृषि मंत्रालय की अनुदानों पर बोलने का अवसर दिया । मैं इनका समर्थन करता हूं साथ ही साथ सुझाव भी दूंगा । कृषि का कार्य पिछले दो सालों में काफी अच्छे ढंग से चलाया जा रहा है जिसके लिए मैं कृषि मंत्री और उनके मंत्रालय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस अवधि में कृषि मंत्रालय के जितने भी इन्फ्रा स्ट्रक्चर हैं उनको सुदृढ़ करके पैदावार को बढ़ाया है ।

इसी सदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि कृषि उत्पादन में कोआपरेटिव स्ट्रक्चर बहुत सहायक है । सारे देश में सहकारिता आन्दोलन के माध्यम से कृषि के विकास में बहुत बड़ा सहयोग और सहायता प्रदान कर रहा है ।आप जानते हैं सहाकारिता आन्दोलन अपने आप में कोई साध्य नहीं है, लेकिन साधन है जो कृषि विकास के कामों में सहायता प्रदान करता है । सारे सारे देश में लगभग साढ़े 3 लाख कोआपरेटिव सोसाइटियां ग्रामीण स्तर से ले कर जिला राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक हैं । साढ़े 3 लाख समितियां में से लगभग सवा लाख गावां के स्तर पर हैं जो कृषि विकास में क्रेडिट या अन्य साधन कृषि की उपयोगिता का ध्यान में रख कर मुहैया करती हैं । सारे देश में कोआपरेटिव क्षेत्र में 337 सेण्ट्रल कोआपरेटिव बैंक हैं जो किसानों को पूंजी की आवश्यकता होती है चाहे बैल खरीदने के लिए या इमप्लीमेंट्स पेस्टोसाइड्स या फ़र्टिलाइज़र्स खरीदने का काम हो, इन सब कामों के लिए सेण्ट्रल कोआपरेटिव बैंक से फ़ाइनेन्स होता है । लगभग 97 परसेंट गांव सहकारिता के क्षेत्र में आ गये हैं बड़े व्यापक ढंग से सहकारिता के माध्यम से कृषि के विकास और विस्तार के काम देश में चलाये जा रहे हैं । सारे राष्ट्र में 27 स्टेट कोआपरेटिव बैंक हैं जो पैसे की व्यवस्था कर के सेण्ट्रल कोआपरेटिव बैंक के माध्यम से ग्राम समितियां के द्वार अपने सदस्यों को मुहैया कराते हैं । इसी तरह से नेशनल लेविल पर भी 19 राष्ट्रीय स्तर की कोआपरेटिव सोसाइटियां हैं । इसमें नाफ़ेड मारकेटिंग सैक्टर में सब से बड़ी कोआपरेटिव सोसाइटी है । एन० सी० सी० एफ० कंज्यूमर के क्षेत्र में बड़ी सोसाइटी है । इफ़को इडस्ट्री के क्षेत्र में सब से बडी इडस्ट्री है जो फ़र्टिलाइज़र्स बनाती है । इसी तरह से अनेक राष्ट्रीय स्तर पर समितियां ऐग्रीकल्चर के विकास और विस्तार के काम में लगी हुई हैं । इनका इनफ्रास्ट्रक्चर जो सहकारिता के क्षेत्र में मारकेटिंग और प्रोसेसिंग की सहायता करने के लिए है उसमें एक सस्था एन० सी० डी० सी० है ।

वह काफी तत्परता और कर्मठता के साथ अपना काम आगे बढ़ा रहा है । इस छठी पंचवर्षीय योजना में मार्केटिंग और प्रासर्सिंग के काम को बढ़ाने के लिये 460 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जिसमें लगभग 1981–82 में 160 करोड़ रुपया अभी तक कोल्ड स्टोरेज और स्टोरेज की फैसिलिटी बढ़ाने के है । सारे कंट्री में स्टोरेज फैसिलिटी अच्छी न होने के कारण बहुत-सा हमारा अन्न बरबाद हो जाता है जिसे चूहे और कीड़े खाते हैं । आज भी वह प्रावलम बड़े पैमाने पर है ।

मैं एन० सी० डी० सी० के लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वर्ल्ड बैंक की सहायता के सारे कंट्री में कोल्ड स्टोरेज की अच्छी सुविधा की गई है । जो आलू आज हिन्दुस्तान में किसान पैदा करता है, खास कर यू०पी०, पंजाब, हरियाणा, बिहार में आलू का उत्पादन बढ़ गया है, कृषि विभाग के सहयोग और सहायता से, लेकिन स्टोरेज फैसिलिटी न रहने के कारण किसानों को डिस्ट्रेस सेल करना पड़ता है । इस साल यू पी० में किसान का 10 रुपये मन आलू बिका जिसको कहा जा सकता है कि हार्वेस्टिंग कास्ट भी नहीं आया । एन० सी० डी० सी० के बड़े पैमाने पर वर्ल्ड बैंक की सहायता से कोल्ड स्टोरेज और रूरल गोडाउन्स है, जो किसानों को सुविधा देने का काम कर रहे हैं और यह बड़ा सराहनीय है ।

अभी तक सारे कंट्री में 137 कोल्ड स्टोरेज बनवाये हैं और वर्ल्ड बैंक की इन्होंने सहायतासे बड़े पैमाने पर इनकी केपैसिटी 38 लाख टन और बढ़ जायेगी । इसलिये "कृषि मंत्रालय" को इन इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ।

एन० सी० डी० सी० की ओर से को-आपरेटिव के क्षेत्र में चीनी मिल, वनस्पति मिल और स्पिनिंग मिल बैठाने की बड़ी भारी योजना है । इस बार 63 स्पिनिंग मिल सहकारिता के क्षेत्र में एन० सी० डीड सी० के माध्यन से बनाने की योजना है जिसमें यह चाहते हैं कि 38 ऐसे स्थानों पर बने जहां कि हमारे वीवर्स की संख्या ज्यादा है, 26 ऐसे स्थानों पर बने, निर्मित हों, जहां कि हमारे काटन उत्पादकों की संख्या ज्यादा है । लेकिन मैं कृषि मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इनकी संख्या में वृद्धि होनी चाहिए । आप जानते हैं कि चीनी के उत्पादन के मामले में सहकारिता क्षेत्र का बहुत ही इम्पार्टेन्ट रोल है । 154 चीनी मिल एन० सी० डी० सी० की सहायता से सारे कंट्री में बनाई गई है । देश में जो चीनी का उत्पादन हैं, उसका 57 परसैंट हमारे सहकारिता क्षेत्र में है । में आग्रह करना चाहूंगा कि अपने सहकारिता मंत्री जी से कि उन्होंने छठी योजना में सहकारिता के क्षेत्र में चीनी मिलों के लाइसेंस देने की व्यवस्था जो की है, लेकिन अभी छठी पंच-वर्षीय योजना के शुरू में प्रारंम्भिक काल में केवल 20 मिलें देने की चर्चा योजना के अन्तर्गत की गई है ।

मैं चाहूंगा कि चीनी मिलों का विस्तार हो और चीनी के उत्पादन को बढ़ाया जाय आप जानते हैं कि पिछले वर्षो में जब चीनी की कमी हुई, तो हमें फिर से चीनी का इम्पोर्ट करना पड़ा । अब चीनी की स्थिति सुधरी है । सहकारिता क्षेत्र के कार्यकर्ता चाहे वे गैर-सरकारी कार्यकर्ता हों और चाह मिलों में काम करने वाले हों, उत्पादन में बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं । मैं चाहता हूं कि चीनी मिलों का जाल बिछाया जाय, और खासकर बिहार में तीन चार चीनी मिलों की स्वीकृति दी जाये, जो हम सहकारिता क्षेत्र में स्थापित कर सकें ।

एन० सी० डी० सी० वनस्पति मिलों के लिये भी सहायता करता है । अभी चार वनस्पति मिलों की योजना है : तीन चालू

[श्री तपेश्वर सिंह]

हैं और एक अभी चालू नहीं है । उसमें नये फंड देने की चर्चा की गई , लेकिन यह नहीं बताया गया है कि कितना दिया जायेगा । मैं कृषि मंत्री महोदय से मांग करना चाहता हूं कि सहकारिता के क्षेत्र में और वनस्पति मिलों की स्वीकृति दी जाए । आज सारे देश में वनस्पति मिलें प्राईवेट ट्रेड के साथ में है । प्राईवेट ट्रेड जब चाहता है, तब देश में हाहाकार मचवा देता है । आज बिहार में वनस्पति तेल की भारी कमी है । वहां पर एक टीन पर पचास-पचास रुपये की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है । मैं भारत सरकार और कृषि मंत्री से आग्रह करूंगा कि सहकारिता के क्षेत्र में और वनस्पति मिलों की व्यवस्था की जाय, ताकि देश में वनस्पति के अभाव को दूर किया जा सके ।

एक बड़ा भारी प्रश्न है सहकारिता आन्दोलन का । चूंकि कृषि मंत्री सहकारिता मंत्री भी हैं, इसलिये मैं उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि को-आपरेटिव का एसेंस है डेमोक्रसी, प्रजातंत्र । जिस को-आपरेटिव में प्रजातंत्र न हो, जिसमें एपायंटिड लोग हों, उसे कोआपरेटिव की संज्ञा नहीं दी जा सकती, उसे कारपोरेशन कहा जा सकता है । सहकारिता समिति सदस्यों की समिति होती है । सदस्यों को चुनाव करने का अधिकार होना चाहिये । जब मैं कृषि मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि जिस राज्य में चुनाव नहीं हो रहा है, वहां चुनाव कराए जाएं, तो यही कहा जाता है कि कोआपरेटिव एक स्टेट सबजेक्ट है, इसलिये स्टेट गवर्नमेंट्स को ही चुनाव कराने का अधिकार है ।

आज यू० पी० के सारे कोआपरेटिव इंस्टीट्यूशन अंडर सुपरसेशन हैं । सुपरसेशन का ला यह है कि अगर मैनेजमेंट कोई मिसमैनेजमेंट करता है, तो उसको सुपरसीड किया जाए । लेकिन पोलीटिकल कनसिडरेशन से सुपरसेशन किया जाता है । यू० पी०, तामिल नाडु, मध्य प्रदेश और वैस्ट बंगाल में यही स्थति है । सहकारिता आन्दोलन का एक सिपाही होने के नाते मैं मांग करता हूं कि सहकारिता समितियों में डेमोक्रेसी को रेस्टोर किया जाए । सब जगह यह मांग है कि डेमोक्रसी को रेस्टोर किया जाए । तो फिर कोआपरेटिव के साथ ही क्यों अत्याचार और अन्याय किया जा रहा है और क्यों उसकी डेमोक्रेसी को तबाह करके रखा जाता है ।

I seek your protction, I seek your intervention. The Central Government should take the initiative to conduct elections for the cooperative institutions in the whole of the country.

इस संदर्भ में मैं मांग करता हूं कि कोआपरेटिव को बहुत दिनों तक स्टेट सबजेक्ट बना कर इसका सत्यानास किया गया है, अब इसको सैंट्रल सबजेक्ट बनाया जाए और कांस्टीट्यूशन में एमेंडमेंट करके इसे कान्करेंट लिस्ट में लाया जाए । को-आपरेटिव में 20,000 करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है । हिन्दुस्तान के 69 करोड़ लोगों में से 12 करोड़ परिवार इसके सदस्य हैं । इसके साथ यह खिलवाड़ होता है । मेरी मांग है कि इस को कान्करेंट लिस्ट में लाया जाय ।

एक और मांग रखना चाहता हूं । इस देश की महान नेता हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने काफी पहले आज से लगभग 7 साल पहले जब हमारे जैसे लोगों ने मांग की कि सहकारिता आन्दोलन का डिआफिशियलाइजशन हो तो उन्होंने कहा कि कोकोआपरेटिव मूवमेंट का डिपोलिटिकलाइजेशन भी करना चाहिये । लेकिन उसके बजाय कोआपरेटिव मवमेंट

आज पालिटिशियन्स का एक टूल बनता जा रहा है । मैं यह मांग करना चाहता हुं कि इस कोआपरेटिव मूवमेंट को जनतांत्रिक संस्था के रूप में काम करने दिया जाय । उसमें जो काम करने वाले लोग हैं उनकी उसे मैनेज करने दिया जाय । यह नहीं कि सुपरसीड करके उस पर किसी को बैठा दिया जाय । मैं मांग करता हूं कि एक कमीशन बनाया जाय और इसकी जांच करायी जाय कि जो सुपरसीड करके नामिनेटेड लोगों के द्वारा, आफिसरों के द्वारा जो कोआपरेटिव चलायी गई उसकी आज क्या हालत है, नान-आफिशियल निर्वाचित लोगों के जरिये चलायी जा रही है, वह कैसे चलायी जा रही है ।

एक बहुत महत्वपूर्ण बात की ओर आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । आप की अध्यक्षता में इसी सदन में हम लोगों ने नवार्ड, नेशनल बैंक फार एग्रीकल्चरल एंड रूरलस डेवलपमेंट का बिल पास किया । इसमें यह मांग हमारी बहुत पहले से चली आ रही थी—सहकारिता आन्दोलन में मैंने पहले ही कहा कि कृषि के विकास और विस्तार के क्षेत्र में काम करता है और यह जो बैंक नवार्ड बन रहा है, इसमें कोआपरेटिव को उससे दूर रखने की चेष्टा की गई है । कृषि और कोआपरेटिव दोनों का चोली दामन का साथ है । दोनों एक साथ मिल कर चलने वाले हैं । तो उस को कैसे अलग रखा जा रहा है ? केवल दो डायरेक्टर की व्यवस्था उसमें की गई है । मैं मांग करता हूं कि 50 परसेंट रिजर्व बैंक या भारत सरकार के शेयर होल्डर्स हों और 50 परसेंट सहकारी क्षेत्र के लोग उसमें मेम्बर हों । ईक्विटी मेम्बरशिप हमें दी जाय । यह हमारी मांग है और मैं विश्वास करता हूं कि भारत सरकार इस पर विचार करेगी ।

एक और अत्यन्त आवश्यक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं । आप को पता है कि एन० टी० सी० मिल के संबंध में हमारे देश की नेता और प्रधान मंत्री का यह निर्णय था कि गरीब लोगों के लिये इसके अन्दर सस्ते दर पर कपड़ा बनाया जायगा और सस्ते दर पर वितरण किया जायेगा । उस का वितरण कन्ज्यूमर कोआपरेटिव सोसाइटी के जरिये किया जायगा । हिन्दुस्तान में कन्ज्यमर कोआपरेटिव मूवमेंट काफी आगे बढ़ रहा है और बड़ी भारी संख्या में, लाखों से ऊपर की संख्या में लोग ग्राम स्तर से लेकर ऊपर तक कन्ज्यूमर कोआपरेटिव सोसाइटी में काम कर रह हैं । लगभग 100 करोड़ रुपये का कपड़ा एन०टी०सी०बनाती थी और सस्ते दर पर गरीब भाईयों में इन कोआपरेटिव सोसाइटियों के जरिये उस का वितरण होता था । भारत सरकार की सब्सीडी थी लेकिन 6 महीने पहले एकाएक लगभग ढाई सौ परसेंट दाम बढ़ा दिये गये जिसका परिणाम यह है कि आज बाजार में एन टी सी०का कपड़ा मंहगा है और प्राइवेट टेक्सटाइल फैक्टरीज का कपड़ा सस्ता है । मैं मंत्री जी से मांग करूंगा कि वे सिविल सप्लाइज के भी मंत्री हैं और सिविल सप्लाइज में यह आइटम आता है तथा कोआपरेटिव से यह वाइटली संबंधित है, अतः व इस पर पुनर्विचार करें तथा इर्रेशनल ढग से जो कंट्रोलल्ड क्लाथ के दाम बढ़ा दिये गये हैं उनमें सुधार लाय ताकि गरीबों को यह उपलब्ध हो सके ।

श्री सूर्य नारायण सिंह (बलिया) : उपाध्यक्ष महोदय, कृषि के क्षेत्र में इस सरकार ने जिन नीतियों को चलाने का प्रयास किया है उसका लाजमी नतीजा यह निकला है कि कृषि की पैदावार में गतिरोध की स्थिति पैदा हो गई है । 1978–79 में 131.90 मिलियन टन खाद्यान्न पैदा हुआ । 1979–80 में 109.70 मिलियन टन खाद्यान्न पैदा हुआ । 1980–81 में 129.87 मिलियन टन अनाज पैदा हुआ ।

[श्री सूर्य नारायण सिंह]

1981–82 का जो लक्ष्य रखा गया है वह पूरा होने वाला नहीं है । अनुमान है 5 मिलियन टन का शार्ट-फाल होगा । इसके परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की उपलब्धता घटटी चली गई है । 1979 में 435.4 ग्राम से घटकर 420.4 ग्राम की उपलब्धता रह गई । इसी तरह से दलहन के मामले में 1979 में 44.9 ग्राम से 1981–82 में 39.1 ग्राम की उपलब्धता प्रति व्यक्ति रह गई । यह स्थति गतिरोध की चल रही है ।

एक तरफ सरकार पैदावार बढ़ाने की बात करती है । सरकार ने घोषणा की है कि वह 1982 को प्रोडक्टिविटी ईयर के रूप में मनाने जा रही है लेकिन प्रोडक्शन बढ़ाने के सिलसिले में सरकार की नीति क्या है ? आप जानते हैं कि पिछले साल लगातार पूरे देश के पैमाने पर किसानों की ओर से शोर मचाया गया और उन्होंने मांग की कि गेहूं की कीमत बढ़ाई जाय लेकिन सरकार ने 135 रुपये प्रति क्विंटल कीमत निर्धारित की । परिणामस्वरूप सरकार ने जो उगाही का लक्ष्य रखा था वह पूरा नहीं हो सका क्योंकि सरकार ने कीमत कम रखी थी और किसानों को घाटा हो रहा था । उसके बाद सरकार की ओर से 15 लाख टन गेहूं का आयात किया गया । आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि सरकार को उस आयात पर 99 करोड़ का अतिरिक्त खर्चा करना पड़ा । अगर देश में ही गेहूं का दाम 135 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये क्विंटल कर दिया जाता तो उसमें केवल 18 करोड़ का ही अतिरिक्त खर्चा सरकार को करना पड़ता और किसान खुशी से सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पूरा कर देते तथा विश्व की बाजारों पर हमारी निर्भरता भी कम होती । साथ-साथ हमारे देश के किसानों को पैदावार बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन भी मिलता ।

एक तरफ तो कृषि के लिये फर्टिलाइजर तथा दूसरे इनपुटस की कीमत लगातार बढ़ती गई हैं । आप देखेंगे कि 1979 में यूरिया के दाम 1450 रुपये प्रति टन से बढ़कर 1981 में 2350 रुपये हो गये हैं । इसी प्रकार से किरोसिन, डीजल तथा अन्य इनपुट्स के दाम भी बढ़ाये गये हैं । खेती के इनपुट्स के दाम तो 62 प्रतिशत बढ़े हैं लेकिन धान और गहूं के दामों में सरकार ने केवल दस परसेंट का ही इजाफा किया है । इस प्रकार से किसानों को अपार क्षति का सामना करना पड़ा है ।

आप कहते हैं कि हम पैदावार बढ़ाएंगे पैदावार बढ़ाने के लिए अगर इनपुट्स के दामों को कम नहीं किया गया और उस को उस स्तर तक नहीं गिराया गया जिस पर आसानी से लोग खरीद सकें और किसानों को उन की फसल का लाभकारी दाम अगर नहीं मिला, तो आप का जो मंसूबा कृषि की पैदावार बढ़ाने का है, वह कभी पूरा नहीं हो सकता । आप ने इस बात की घोषणा की थी कि कृषि की पैदावार को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर सिंचाई की योजनाओं का विस्तार किया जाएगा, लेकिन आज स्थिति क्या है कि विस्तार करने की बात तो अलग रही, अभी जो सिंचाई की क्षमता है, उस का उपयोग किस रूप में हो रहा है, यह आप जानते हैं । बिहार में सिंचाई की जो योजनाएं पूरी की जा चुकी हैं और जो बड़े पैमाने पर ट्यूबवेल्स लगाए गये हैं, उन की स्थिति क्या है ? उन की स्थिति यह है कि भ्रष्टाचार की वजह से जो ट्यूबवेल्स लगाए गए हैं, उन के नालों का विस्तार नहीं हो सका है । ठेकेदारों और अफ़सरों, इन दोनों के भ्रष्टाचार से कमांड एरिया में जितनी सिंचाई हो सकती है, उस क्षमता का भी उपयोग नहीं हो सका है ।

बाढ़ से सुरक्षा के नाम पर गंगा, गंडक और बलान में आप ने बांध लगाए हैं लेकिन पानी के निकासी के जो प्राकृतिक

स्रोत थे, वे रास्ते अवरुद्ध हो गये हैं और आप ने पानी के निकासी का कोई इन्तज़ाम नहीं किया है । बिहार में सिर्फ एक जिला बेगूसराय के बारे में मैं कह सकता हू कि पचासों हज़ार एकड जमीन में जल जमाव की वजह से फ़सलें बरबाद हो जाती हैं । आप सिचाई की सुविधाए देने की बात करते हैं लेकिन पानी के निकासी का इन्तज़ाम नहीं करते । सिचाई की सुविधाए दे कर आप खेतो की पैदावार बढ़ाना चाहते हैं मगर वास्तविकता दूसरी है, तस्वीर दूसरी है और नतीजा यह है कि पैदावार का निरन्तर ह्रास हो रहा है और आप पैदावार के लक्ष्य किसी भी कीमत पर एचीव नहीं कर सकते ।

देहाती की क्या स्थिति है, ग्रामीण जीवन की क्या वास्तविकता है ? कितने दिन हो गये कि आप ने लैंड रिफार्म्स के कानून बनाए, लैण्ड सीलिंग के कानून बनाए मगर कितनी जमीन आप ने अभी तक बांटी है । मात्र 18 लाख एकड जमीन बांटी है जब कि नेशनल सैम्पिल सर्वे के अनुसार 215 लाख एकड़ सरप्लस जमीन है । इस जमीन का अभी तक बटवारा नहीं हुआ । आज ऐसे अनेक क्षेत्र हैं, जिन के लिए आप कानून के अन्तर्गत कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कर सके, जिस से दृढ़ता के साथ वह कानून लागू किया जा सकता । आप ऐसे अफ़सरों का मुहय्या नहीं कर सके, जो प्रतिबद्ध हों लैण्ड रिफार्म्स लागू करने के लिए । आज तो हालत यह है कि कानून के अलमबरदार या पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर सका जब कि हज़ारों हज़ार शेयर-कौपर्स की बेदखल कर दिया गया । बेदखली पर रोक लगाने के लिए आप सक्षम कानून बना सकते थे । आज ऐसे कानून का नितान्त अभाव है । जो कानून बनाए हैं, वे किस की मदद से लागू होंगे ? वे इन्हीं लोगों की मदद से लागू होंगे लेकिन आप यह देखें कि बड़े पैमाने पर बेदखलियां हुई हैं और पुलिस प्रशासन, जिसकी जिम्मेदारी थी बेदखली रोकने की, आज वह खुल्लम-खुल्ला भुस्वामियों की मदद कर रहा है। मैं आपका एक इस्टांस इस सिलसिले में देना चाहता हू ।

हमारे बिहार में खगरिया जिले में माहनपुर पंचायत के अग्रहन ग्राम में बटाईदारों को जमीन के पर्चे मिले और वे जमीनों पर बेदखली रोकने के लिए गये, तो पुलिस जो उन की जमीनों पर खड़ी थी, वह इसलिए नहीं खड़ी थी कि बटाईदारों को कैसे सुरक्षा प्रदान की जाए बल्कि वह उन लोगों की मदद के लिए थी जो बटाईदारों को जमीनों से बेदखल करना चाहते थे और बटाईदारों का नेता मेदनी शाह को जमींदारों के गुंडों ने नहीं पीटा बल्कि पुलिस ने लगातार उस पर लाठियों की वर्षा की और पुलिस की लाठियों से चोट खाकर जमीन पर तड़पता रहा और तकलीफ़देह बात तो यह है कि उस की पत्नी वहां खड़ी थी और वह देख रही थी कि उस के पति की हत्या किस तरह की जा रही है । यह है आप का पुलिस प्रशासन और आप के प्रतिबद्ध अफ़सर, जिनके द्वारा आप लैंड रिफार्म्स के कानूनों को लागू करवाना चाहते हैं । अभी कुछ दिन पहले, उसी पंचायत में एक घटना और घटी । एक हरिजन लड़की, जिस की उम्र 18–20 साल रही होगी, आप को मालूम होगा कि उस के साथ क्या हुआ । वे लोग जो जमीन की बेदखली करने वाले लठैत थे, उन्होंने उस के साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर डाली उसकी जमीन पर और जिस दारोगा ने मेदनी शाह की हत्या की थी और जन-आक्रोश ने संगठित रूप जब धारण किया था, तो उस दारोगा को वहां से हटाया गया था लेकिन पालीटीकल प्रोटेक्शन और पालीटीकल

[श्री सूर्य नारायण सिंह]

इण्टरफियरेन्स की वजह से उस दारोगा का उसी जगह पर पदस्थापन कर दिया गया, उस को उसी थाने में वापस बुला लिया गया। वहां पर ऐसा हुआ है और आप हरिजनों के नाम पर आंसू बहाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं। भूमि सुधार कानूनों और हरिजनों के नाम की यह सरकार दुहाई देती है। लेकिन आज क्या हो रहा है? हरिजनों के साथ अत्याचार और अत्याचार करने वाले दारोगा को उसी इलाके में स्थापित किया गया है जहां कि किसानों का आन्दोलन जमीन के बंटवारे के लिए हो रहा है।

हमारे सत्तारूढ़ दल के भाई कहते हैं कि विरोधी पक्ष का यह पेशा बन गया है कि वह हर सवाल पर सरकार की आलोचना करे। आप जानते हैं कि गांवों के अन्दर आज क्या स्थिति हो रही है? आज यह स्थिति है कि 35 वर्ष की आजादी के बाद भी भूमि सम्बन्धों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। गांवों के मुट्ठीभर लोग, 10 परसेंट बड़े-बड़े किसान 53.3 परसेंट जमीन को समेटे हुए हैं और वहां का विशाल जनसमुदाय, यानी 60 परसेंट लोगों के पास मुश्किल से 9 फीसदी जमीन होगी। लघु किसान सीमांत किसान जो मेहनत कर के पैदावार बढ़ाना चाहते हैं उनको आपकी योजनाओं का कितना लाभ मिल पाता है, क्या कभी आपने इसको देखा है? इन लघु और सीमांत किसानों को आप सिंचाई और खाद की कितनी सुविधाएं दे पाये हैं? हरित क्रान्ति के नाम पर जो भी आपने खर्च किया है उसका बहुत बड़ा हिस्सा गांव के बड़े बड़े भूस्वामियों ने हड़प लिया है। ऐसी स्थिति में पैदावार बढ़ाने की बात सोची भी नहीं जा सकती।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि आप के अधिकारीगण भूमिसुधार कानून लागू करने से इन्कार करते हैं, बटाईदारों को कानूनी संरक्षण देने से इंकार करते हैं, जमींदारों की जमीनों का बंटवारा करने से इंकार करते हैं। छोटे किसान सिंचाई की सुविधाओं से वंचित रहते हैं, और दूसरी सुविधाएं भी उनको नहीं मिल पाती हैं।

आप जानते हैं कि आज औद्योगिक माल की कीमतें बढ़ती जाती हैं जब कि उसी अनुपात में किसानों की पैदावार की कीमत नहीं बढ़ पाती है। इस से उद्योग और कृषि में पैदावार की कीमतों में डिस्पैरिटी बहुत बढ़ गई है। उस डिस्पैरिटी की क्या हालत है? पिछले 4–5 वर्षों में किसानों की 13 हजार 69 करोड़ रुपये की नुकसान हुआ है। आप दावा करते हैं कि आपकी सरकार किसानों की सरकार है और वह किसानों के लिए काम करती है।

हमारे देश का कृषि मुख्य उद्योग है। यह हमारे देश को प्रगति के रास्ते पर बढ़ाने का काम करता है। किन्तु नतीजा क्या हो रहा है? आज सरकार ने ईयर आफ प्रोडक्टिविटी की घोषणा की है, पैदावार बढ़ाने की घोषणा की है, सिंचाई और दूसरे साधनों के प्रसार और फैलाव की घोषणा की है। मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी निर्भरता विदेशी बाजारों पर घटे और देश में गल्ले की पैदावार बढ़े। हम अपने गल्ले का निर्यात कर सकें और विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकें इसलिए आप लघु और सीमांत किसानों की सभी सहायता दीजिए। उन्हें सिंचाई की, बीज की, ऋण की, खाद की सभी सहायता दीजिए और भूमि सुधार कानूनों का सख्ती से लागू कीजिए। ये कानून जन प्रतिनिधियों की देखरेख में, चुनी हुई समितियों की देखरेख में लागू कीजिए। तभी सही मानों में भूमि का वितरण आप कर सकेंगे। वरना इस से कृषि के विकास को आगे बढ़ाने का सपना

आपका पूरा नहीं होगा और न हमारा देश आगे बढ़ सकेगा ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Every hon. Member shall not take more than 10 minutes and the hon. Minister will have to reply round about 2.30 or 3 P.M. Therefore, please cooperate.

Now, Shri Shailani.

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : माननीय उपाध्यक्ष जी, यह कैसी विडम्बना है कि जिन लोगों ने अपनी निजी गाथाएं व्यक्त की हैं उनसे 20, 25 मिनट बुलवाया गया है । मैं इस देश और इस देश की जनता की बात करना चाहता हूं तो आप मुझे सीमा में बांधना चाहते हैं । मैं अपनी निजी बात कहने के लिए नहीं आया हूं । इस देश के किसानों, ग्रामीणों की जो समस्याएं हैं उनसे सम्बन्धित बात करने आया हूं ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

हमारे देश की महान नेता, प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने नए बीस सूत्री कार्यक्रम में ग्रामीण की आकांक्षाओं और आशाओं को नया बल प्रदान किया है और वे उसमें अपने सुनहरे भविष्य के सपने देखने लगे हैं । यह कार्यक्रम हमारे विकास की आधारशिला है ।

श्री मन्, हमारा देश कृषि प्रधान देश है । इस देश में 75 से ले कर 80 फीसदी जनता गांवों में रहती है और किसी न किसी रूप में कृषि पर निर्भर करती है । हमारे यहां भूमिहीनों की ज्वलंत समस्यायें हैं । आज किसान के नाम पर इस देश में ऐसे-ऐसे लोग हैं जिनके पास एक-एक हजार और 5-5 हजार एकड़ भूमि है और ऐसे लोग भी हैं किसान के नाम पर जिनके पास एक इंच जमीन भी नहीं है । जब किसान की बात आती है तो मैं किसान उस व्यक्ति को मानता हूं जो अपने हाथ से खेत में हल चलाता है, जो सर्दियों के कड़े जाड़े में खेत में पानी लगाता है और कड़ी धूप में वहां पर गेहूं से दाना निकालता है, उसको मैं किसान मानता हूं जो परिश्रम करता है ।

इस देश में किसानों की बहुत सी समस्याएं हैं और उन्हें पूरा करने के लिए मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो बीस सूत्री कार्यक्रम तैयार किया है, उससे अवश्य राहत मिलेगी ।

13.57 hrs.

[SHRI HARINATH MISRA *in the Chair*]

मान्यवर, इस देश में एक अर्से से भूमि सुधार की मांग चली आ रही है कल-परसों और आज भी अखबारों में निकला है कि योजना आयोग ने इस बात पर बड़ा रोष और क्षोभ प्रकट किया है कि इस देश में जिस तरह से भूमि सुधार होना चाहिए, उस तरह से नहीं हो पा रहा है । योजना आयोग ने बार-बार राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वह भूमि सुधार करे, लेकिन मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि योजना आयोग के निर्देश के बावजूद इस देश में भूमि सुधार अभी तक नहीं हो पाया । इसकी वजह यह है कि कहीं-कहीं पर सरकारें बड़े-बड़े जमींदारों, राजा-महाराजाओं और जो हजारों एकड़ भूमि के मालिक हैं, उनके दबाव में है । इस वजह से भूमि सुधार नहीं हो पा रहा है । इसी प्रकार जहां भूमि का आवंटन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को किया गया है, गरीबों और भूमिहीनों को किया गया है, उनको आज तक कब्जा नहीं दिया जा रहा है और पट्टा उनका नहीं दिया जा रहा है । जहां

[श्री चन्द्रपाल शैलानी]

नाममात्र के पट्टे कर दिए गए हैं, लेकिन कब्जा नहीं दिया जा रहा है ।

यहां पर ऊसर और बंजर भूमि का सवाल भी कई बार आया है । मैं अलीगढ़ जिले का रहने वाला हूं । अगर आप कभी रेलगाड़ी से या सड़क से कानपुर की तरफ़ यात्रा करेंगे तो अलीगढ़ से निकलते ही आप पाएगें कि दोनों तरफ़ बेहद ऊसर और बंजर जमीन पड़ी हुई है । हमारे अलीगढ़ जिले में ही 80 हजार एकड़ ऊसर और बंजर भूमि है, जिसका कोई सदुपयोग नहीं हो रहा है और बेकार पड़ी हुई है । अगर उसको उपजाऊ बनाया जाए तो मैं समझता हूं कि इस देश के उत्पादन में काफी वृद्धि होगी । अलीगढ़ से लेकर एटा, मैनपुरी, इटावा, कानपुर आदि जिलों में लाखों हैक्टेयर जमीन ऊसर तथा बंजर पड़ी हुई है । उसको उपजाऊ बनाने के लिए अभी तक कोई कारगर कदम नहीं उठाया जा रहा है ।

मान्यवर, मैं खेतीहर मजदूरों की समस्याओं पर आता हूं । खेतीहर मजदूरों में ज्यादातर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं। इस देश में अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर जुल्म और अत्याचारों की जो भरमार हो रही है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उनके पास जमीन नहीं है । हमारी सरकार चाहती है, उसका इरादा है और हमारी सरकार ने बहुत कुछ किया भी है, लेकिन वहां पर सबल जमींदार और बड़े लोग उनको उस अधिकार से वंचित रखे हुए हैं । अगर उनकी ये समस्यायें हल नहीं हुई तो ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है कि उन में किसी और प्रकार की भावना पैदा हो । खेतीहर मजदूर जो खेत में काम करता है, मेहनत करता है, बच्चों के साथ, स्त्रियों के साथ मिल कर खेत में काम करता है, उनकी समस्याओं को गम्भीरता से लिया जाना चाहिए और उनको हल किया जाना चाहिए ।

14.00 hrs.

सरकार ने किसानों को सुविधायें देने लिए बहुत से उपाय किए हैं, बहुत-सी एंजसियां जुटाई हैं लेकिन वहां पर जिस कद्र भ्रष्टाचार है, जिस तरह से उनकी दुर्दशा होती है उसका एक उदाहरण मैं आपकी सेवा में रखना चाहता हूं । सरकारी ऋण लेने में उसका शोषण किस तरह से किया जाता है इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । मैं किसान उसको मानता हूं, जैसा मैंने पहले निवेदन किया है, जो अपने हाथ से हल चलाता है, खेत में मेहनत करता है, काम करता है । हमारे देश का दुर्भाग्य यह है कि किसान कर्ज में पैदा होता है और कर्ज में मरता है । श्रीमती इंदिरा गांधी के राज में, शासन काल में, उनकी मेहरबानी से किसान ने कुछ चैन की सांस ली है । लेकिन फ़िर भी उसको अपनी खेतीबाड़ी के लिए, अन्य कामों के लिए साहूकार के पास, महाजन के पास जाना पड़ता है । हालांकि बैंकों ने ऋणों की व्यवस्था की है, ऋणों की सुविधा दी है लेकिन वही एक साधन पर्याप्त नहीं है । बैंकों से ऋण लेने में उनको कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ता है इसको भी आप देखें । उसको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है । जितना ऋण उनको सैंक्शन होता है, उसका कितना भाग उसको मिल पाता है, यह तथ्य मैं आपकी सेवा में रखना चाहता हूं । पम्पिंग सैट, ट्यूबवैल, बैल खरीदने के लिए या और इस तरह का कोई ऋण लेना होता है तो किसान को अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ती है । उसके बाद ऋण प्राप्त करने के लिए उसका चक्कर पर चक्कर लगाने पड़ते हैं ।

बैंकों का परसेंटेज बंधा होता है, पांच, दस बीस और पच्चीस प्रतिशत तक । एक हजार रुपये अगर सैंक्शन किए जाते हैं तो किसान को मुश्किल से छः सात सौ रुपये ही मिलते हैं । किसी तरह से वह समय पर अदा नहीं कर पाता है तो बहुत ही बेरहमी के साथ उसके साथ सलूक किया जाता है, उसके घर के बरतन, उसकी पत्नी के जेवरात आदि बेच कर भी उससे पैसा वसूल कर लिया जाता है । यह जो तरीका है बैंकों से ऋण लेने का इसको सुधारा जाना चाहिए ताकि किसानों को, काश्तकारों को ज्यादा फ़ील न हो ।

उर्वरकों की बात कही गई है । दिन प्रति दिन खेती में लागत बढ़ती चली जा रही है । किसान अपनी फ़सल ले कर जब मार्किट में आता है तो अपनी फ़सल का उसको उतना फ़ायदा नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए । मैं इसी फ़सल की बात करना चाहता हूं । आलू और गन्ने की जितनी मिट्टी खराब हो रही है और हुई है, उससे सब लोग अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं । मैं भी एक छोटा सा काश्तकार हूं । मैं कहे बगैर नहीं रह सकता हू कि आलू की पैदावार करने में जितनी लागत लगी है, उससे प्राफ़िट कमाने की बात तो दूर रही जितनी लागत भी लगी है उसका आधार पैसा भी किसान को प्राप्त नहीं हो पाया है । आलू आठ नौ और दस रुपये मन में बिका है जब कि लागत उसकी उससे चौगुनी और पांच गुनी लगी है । मैं चाहता हूं कि—फ़र्टिलाइजर की कीमत आप कम करें । सही वक्त पर उसको ऋण मुहैया करें । इतनी परेशानियों के बावजू, इतनी मेहनत के बावजूद, इतने शोषण के बावजूद, किसान एक कठोर कर्मा इंसान है, किसान से अधिक मेहनत कोई नहीं करता है उससे ज्यादा मुशक्क्त कोई नहीं करता है । लेकिन अफ़सोस की बात है कि इस देश में जो सब से ज्यादा मेहनत करता है, सबसे ज्यादा कटोर कर्मा है, सब से ज्यादा परिश्रम करता है वही सब से ज्यादा दुखी है और जो कुछ भी नहीं करता है—

सभापति महोदय : अब आप समाप्त करें ।.

श्री चन्द्रपाल शैलानी : मैं ने तो अभी शुरू ही किया है । और माननीय सदस्य आध आध घंटा बोले हैं ।

सभापति महोदय : मेरा निवेदन सुन लें । यह आपके लिए ही नहीं है सब के लिए है । जो अन्य माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, उनके लिए भी है । मैं आया अभी । जो लिस्ट डिप्टी स्पीकर मुझे दे गये उसके अनुसार आपके अतिरिक्त 8 सदस्य और बोलने वाले हैं और मंत्री जी 3 बजे जवाब देना चाहते हैं । इसलिए 10 मिनट से ज्यादा पासिबिल नहीं है, और 10 मिनट आप के हो गये । जब तक आप लोग सहयोग प्रदान नहीं करेंगे तब तक मैं क्या कर सकता हूं । आप मेरी लाचारी समझ लीजिए । यह नहीं कि मैं कंजूस हूं, अधिक से अधिक उदार होने की चेष्टा करता हूं । अतः आप सहयोग प्रदान करें ।

श्री चन्द्रपाल शैलानी : इसी सदन के सदस्य आधा घंटा बोले हैं, मुझे तो अभी 6 मिनट ही हुए हैं । फिर भी जल्दी ही अपनी बात समाप्त करता हूं ।

किसानों के सामने सिंचाई की प्रौबलम है । वैसे नहरों और बम्बों का बहुत बड़ा अभाव है, लेकिन सरकार चाहती है कि किसान का उद्धार हो इसलिए जगह जगह ट्यूब वैल लगाये जा रहे हैं, उनको सरकारी सहायता भी इसके लिए मिल रही है । लेकिन किसानों को समय पर

[श्री चन्द्रपाल शैलानी]

बिजली नहीं मिलती, जब कि उद्योग-धंधों को बिजली मिलती है। इस साल गन्ने और आलू का रेकार्ड तोड़ उत्पादन हुआ है। विदेशों में किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए उसकी फसल को सरकार खरीद लेती है भले ही चाहे उत्पादन को समुद्र में डुबाना पड़, जलाना पड़ या कुछ भी करे, लेकिन किसान को उसके उत्पादन का पूरा मूल्य मिल जाता है। इससे उसका उत्साह बढ़ता है। लेकिन यहां पर किसान कर्ज ले कर खेती में लगाता है और जब पूरा मूल्य उसको नहीं मिलता तो उसको हिम्मत टूटती है। लेकिन इसके बाद भी हमारे देश को पैदावार बढ़ रही है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक स्थान हसायन है जहां दुनिया का सबसे उम्दा किस्म का गुलाब पैदा होता है। वह गुलाब नहीं जो बड़े बड़े आदमियों की कोठियों को शोभा बढ़ाता है, बल्कि ऐसा गुलाब है जो देखने में तो अच्छा नहीं होता, लेकिन उससे उच्च कोटि का सेंट, रूह, गुलकंद और गुलाब जल बनता है। हमारे यहां कन्नौज के व्यापारी आते हैं और कौड़ियां के मोल में उसको खरीद ले जाते हैं। इसलिए हसायन क्षेत्र में सरकार कोई ऐसा रिसर्च सेण्टर या कारखाना खोले जिससे बढ़िया से बढ़िया किस्म का इन रूह आदि पैदा हो सके। अभी तो वहां के लोग घरेलू उद्योग धंधो के आधार पर इन चीज़ों को बनाते हैं। अगर फैक्ट्री लग जाय तो करोड़ों रु० की विदेशी मुद्रा मिल सकती है।

ग्रामीण बैंकों को व्यापक बनाया जाय, यह एक बहुत बड़ी योजना है जिससे किसानों को लाभ हो सकता है। ग्रामीण विकास की बात जब आती है तो कहना पड़ता है कि हमारा देश ही एक ऐसा देश है जहां पर गांव के पढ़े लिखे नौजवान गांव छोड़कर शहर की तरफ भागते हैं। जब कि विदेशों में लोग शहर में रहना पसन्द नहीं करते हैं, बल्कि गांव में रहना पसन्द करते हैं। इसके भी कुछ कारण हैं, और वह यह कि ग्रामीण विकास को तरफ हमारा ध्यान बहुत कम गया है। उन्हे साज-सज्जित रखने के लिए मैं चन्द सुझाव देना चाहता हू। मैं हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों का शुक्रगुजार हूं कि वहां पर हर गांव में बिजली और पानी को व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन हमारा देश बहुत विशाल है, यहां ऐसे बहुत से गांव हैं जहां कि अभी भी बिजली नहीं है। मेरा निवेदन है कि हर गांव में बिजली पहुंचाई जाये, गांव को सड़क से जोड़ा जाये, चिकित्सा के लिए अस्पताल खोले जाये, लघु-उद्योग धन्धे खोले जाये, शुद्ध जल और चिकित्सा की व्यवस्था की जाये और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे देश में जातीय और साम्प्रदायिक सद्भावना के लिए प्रयास किये जायें जिससे यहां पर जो जातीय व साम्प्रदायिक दंगे होते हैं, वह न हों और देश में सुरक्षा की भावना पैदा हो। समाज के कमजोर लोगों की सुरक्षा की भी व्यवस्था की जाये।

इन सारी चीजों को व्यवस्था कर दी जाये तो मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यह देश संसार में सबसे आगे की श्रणी में आ जायेगा और खुशहाल होगा और यह देश महात्मा गांधी के सपनों का देश होगा। यहां हर तरह से खुशहाली, वैभव हो सकेगा और हर आदमी सुख व चैन से रहेगा।

इन शब्दों के साथ आपने जो मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री दौलत राम सारण (चुरू): सभापति जी, सबसे विस्तृत मंत्रालय की मांगों से सम्बन्धित मदों पर सबसे कम समय में बोलना पड़ रहा है।

कृषि हमारे देश का आधार है, 80 प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर है और यहां की सारी अर्थ-व्यवस्था भी कृषि पर आधारित है। इस कृषि की जितनी महत्ता और आवश्यकता यहां पर है, उतनी ही घोर उपेक्षा इसकी हुई है ।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में केवल 37 प्रतिशत कृषि क्षेत्र के लिये प्रावधान किया गया था उसके बाद निरन्तर सब योजनाओं में उसका प्रावधान कम होता गया और बड़े उद्योगों में प्रावधान बढ़ता गया। जिन बड़े उद्योगों द्वारा केवल 4 प्रतिशत लोगों को रोजगार मिलता है, उन पर अधिक पैसा लगाया गया और जिस कृषि द्वारा 73 प्रतिशत लोगो को सीधा रोजगार मिलता है, उस पर बहुत थोड़ा पैसा रखा गया। इस कृषि-निवेश में कंजूसी के परिणामस्वरूप यह प्रभाव आया कि खाद्यान्न का भयंकर अभाव हुआ और 73 प्रतिशत कृषि कार्य में लगे हुए लोगों को 4 प्रतिशत खेती में लगे हुए लोगों के देश से अनाज मंगाकर खाना पड़ा। इसका परिणाम यह है कि सरकार गलत नीति पर आ रही है और अभी पिछले वर्ष में भी लाखों टन अनाज बाहर से मंगाया गया है। कृषि पैदावार कई रूप में बाहर से मंगाई जा रही है ।

हमारे यहां दालों और तिलहनों का उत्पादन गिर रहा है। हमारी आबादी बढ़ने के अनुपात में हमारा कृषि उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। हमारे एक भाई ने आंकड़े दे कर बताया था, मैं उसमें न जा कर यह कहना चाहता हूं कि दालें, दूध और अनाज प्रति व्यक्ति घटा है। कपड़ा प्रति व्यक्ति घटा है। एक तरफ यह कहा जाता है कि हम आत्म-निर्भर होने जा रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे यहां अभाव बढ़ता जा रहा है। इसका एक मात्र कारण यह है कि खेती की तरफ कम निवेश किया है, कम ध्यान दिया गया है।

आज 35 वर्ष के बाद भी हमारे देश में केवल 30 प्रतिशत भूमि में पानी पहुंचाया गया है, 70 प्रतिशत भूमि आज भी असिंचित है, इस तरह इस ओर घोर उपेक्षा हो रही है। इस क्षेत्र में बहुत थोड़ा पैसा ऋण के लिये दिया जाता है ?

ज्यादातर शार्ट टर्म पर ऋण दिया जाता है। लम्बी अवधि के ऋण बहुत कम दिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त सहकारिता संस्थाओं को ऋण दिया जाता है। है। अगर वसूली रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अनुपात में नहीं होती है, तो सारे किसानों को ऋण देना बन्द कर दिया जाता है। राजस्थान के जयपुर जिले में, जो कि सब से बड़ा जिला है, जहां बीस लाख लोग रहते हैं, इस प्रकार से ऋण रोक दिया गया है। वहां किसानों को ऋण नही मिल रहा है; क्योंकि भूमि विकास बैंक की वसूली रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित आधार के मुताबिक नहीं है। इसकी तुलना में औद्योगिक क्षेत्र में व्यक्तिगत रूप से ऋण देने पर कोई रोक टोक नहीं है। कृषि क्षेत्र में बकाया ऋण औद्योगिक क्षेत्र के ऋण से कहीं कम है।

खेती के क्षेत्र में ऋण सुविधायें बहुत कम हैं, इसलिये किसान अपनी खेती की पैदावार बढ़ाने में असमर्थ है। सिंचाई के क्षेत्र को बढ़ाने पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नदियां का पानी बह कर बाढ़ के रूप में अरबों रुपये की हानि करता है। उसको खेतों तक पहुंचाने के लिये बड़ी-बड़ी योजनायें नहीं बनाई गई है। ऐसी बहुत सी योजनायें अन्तर्राज्यीय झगड़ों में उलझी पड़ी हुई हैं। नदियों का पानी बह कर नष्ट हो रहा है, लेकिन खेतों को नहीं मिल रहा है। यह सरकार खेती की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है।

इस देश में जब तक आम आदमी की क्रय शक्ति नही बढ़ेगी, तब तक इस देश की माली हालत नहीं सुधर सकती, और आम

[श्री दौलत राम सारण]

आदमी की क्रय शक्ति को बढ़ाने का एकमात्र उपाय खेती की पैदावार को बढ़ाना है । खेती की पैदावार बढ़ने से 80 प्रतिशत लोगों की क्रय-शक्ति बढ़ेगी, जिससे देश का उद्योग, व्यापार और यातायात पनपेगा और उससे खेती पर से भार कम होगा, दूसरे धंधों में ज्यादा लोग लगेंगे और हमारी आर्थिक प्रगति की रफ्तार तेज होगी । लेकिन सरकार की समझ में वह बात नहीं आती, जिसको गांधी जी ने बहुत विस्तार से समझाया था ।

आज गलत आर्थिक नीतियों के कारण खेती की उपेक्षा की जा रही है और बड़े उद्योगों पर धन बर्बाद किया जा रहा है । दिल्ली में केवल दस होटलों पर 400 करोड़ रुपये व्यय किये जा रहे हैं, लेकिन राजस्थान कैनाल, सीधमुख नहर, जमना नहर और नर्बदा से पानी देने की व्यवस्था करने के लिये इस सरकार के पास पैसा नहीं है । गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिये इस सरकार के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन एशियाड पर 1,000 करोड़ रुपये बर्बाद करने के लिये हैं ।

इस सरकार की गलत नीतियों के कारण, ठीक प्राथमिकतायें तय न करने के कारण आज देश के आम आदमी को पोष्ठिक आहार नहीं मिल रहा है । केवल खेती और खेती से संबंधित धंधे ही आम आदमी को पौष्टिक आहार दे सकते हैं । लेकिन आज न अनाज, न दालें और तिलहन न फल सब्जी और न दूध और दूध से बनने वाले पदार्थ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं । हमारे देश के अधिकांश लोग पौष्टिक आहार से वंचित है । हमारे यहां 38 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बिता रहे हैं और वे दोनों समय खाना भी नहीं जुटा सकते ।

खेती की उपेक्षा का सीधा अर्थ है देश की उपेक्षा, देश की अर्थ-व्यवस्था को गलत दिशा देना, आम आदमी की माली हालत को सुधारने से इंकार करना और उसको दर-दर की ठोकरें खाने के लिये छोड़ देना । इस लिये सरकार चलाने वालों से मेरा निवेदन है कि वे खेती की ओर ध्यान दें और खेतों में पानी पहुंचाये और खेती की उपज की बिक्री के लिये बाजार को नियंत्रित करें । आज हालत यह है कि जब फसल आती है, तो भाव एक दम गिरा दिये जाते हैं और जब किसान की फसल बिक जाती है, तो भाव आस्मान को छूने लगते हैं । किसान को हर फसल में खरीद और बिक्री में 200 रुपये प्रति क्विंटल का घाटा होता है । इस तरह की लूट बाजार और मंडियों में चल रही है । किसानों की इस भंयकर शोषण को रोकने की जरूरत है ।

आज हमारे देश में खेती और गैर-खेती के मामले में बड़ा भेदभाव है । गैर-खेती क्षेत्र में, खास तौर से औद्योगिक क्षेत्र में, ऋणों के संबंध में बड़ी उदारता है, बड़ी सुविधा है । लेकिन खेती के क्षेत्र में ऐसा नहीं है । खेती में ऋण अगर बाकी रह जाता है तो तुरन्त सख्ती के साथ कुड़की होती है उसकी जमीन नीलाम कर दी जाती है लेकिन उधर 2 हजार करोड़ से अधिक रुपया औद्योगिक क्षेत्र में बकाया पड़ा है, उस पर कोई कार्यवाही नहीं, क्योंकि वह तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चले जाते हैं । लेकिन ये गरीब किसान किसी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं । वे तो माई बाप कह कर केवल आह भर कर रह जाते हैं । यह हालत खेती करने वाले लोगों की है । खेती की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है ।

समय के अभाव के कारण मैं आकड़ों सहित अपनी बात कहने में असमर्थ हूं ।

परन्तु इतना ही कह देना चाहता हूं कि खेती बढ़ायेंगे तो यातायात, व्यापार उद्योग और रोजगार सभी कुछ बढ़ेगा और पौष्टिक आहार उपलब्ध होगा । आज खेती के संबंध में अनुसंधान और खोज के जो काम किये जा रहे हैं वह सारी खेती के दृष्टि-कोण से नहीं है । केवल 30 प्रतिशत सिंचित भूमि के क्षेत्र में ये अनुसंधान और खोज के कार्य चल रहे हैं । बाकी 70 प्रतिशत भूमि के लिये अनुसंधान का कार्य नहीं के बराबर हैं । इस तरफ भी समग्र विकास की तरफ ध्यान देना चाहिये । मुझे खुशी है कि कुछ प्रयास इस तरफ होने लगा है लेकिन सूखी खेती के क्षेत्र में अभी और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है । वह ध्यान नहीं दिया जा रहा है । फिर हमारे अनु-संधान और रिसर्च का खेतों के साथ ताल मेल नहीं बैठाया गया है । वह अभी तक केवल बड़ी-बड़ी जगहों में ही सीमित है । या तो आपके विश्वविद्यालयों में या अनु-संधान संस्थाओं में यह काम चल रहा है । अभी आज ही प्रश्न के घंटे में पहला ही प्रश्न वन-अनुसंधान के संबंध में था । वनों में पेड़ नहीं हैं और एक तरफ पिसीकल्चर और पेड़ों की खोज पर रुपया खर्च हो रहा है । लेकिन खोज गांवों तक और जंगलों तक पहुंचायी नहीं जा रही है। बहुत से अच्छे बीज और अच्छे पौधों की खोज की गई है लेकिन उसका किसान तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है । तो खेती और अनुसंधान दोनों का तालमेल बैठाने की जरूरत है ।

भूमि का कटाव चाहे पानी से हो चाहे हवा से हो, उसको रोकने की आवश्यकता है । उस पर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है । ऊसर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिये बहुत कम प्रयास किये गये हैं । उसमें भी आप के प्रसास करने की आवश्यकता है ।

इस प्रकार इस सरकार ने कोई संतुलित कृषि विकास का प्रयास नहीं किया है । संतुलित कृषि विकास नहीं करने के कारण.....(व्यवधान).... व्यास जी, उसी के कारण पेट पर ज्यादा जोर पैदा हो गया है, किसी के दांत गिर गए हैं, पौषिष्ट आहार की कमी के कारण यह सब हो रहा है । उसके लिए व्यास जी अपनी सरकार को कहें कि संतुलित विकास की व्यवस्था करे ।

कृषि के उत्तपादन की जितनी क्षमता है, क्षमता के अनुपात में उत्पादन नहीं है । तो क्षमता के अनुरूप उत्पादन हो सके इसके लिए ज्यादा साधन-सुविधा प्रदान करने की जरूरत है । पानी की व्यवस्था की जाए । क्षण: को और क्रय-विक्रय की व्यवस्था की जाय । इसके साथ-साथ अनुसन्धान और इन सारी चीजों का ताल-मेल खेती के साथ बैठाने की जरूरत है और फ़िर कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए इन बुनियादी आधारों की उपेक्षा न कर के अगर व्यवस्था करेंगे तो यह संतुलित नियोजन हो सकेगा ।

केवल अनाज बढ़ाने की तरफ ही ध्यान नहीं देना है, उसके अलावा भोजन के लिए दूसरे आवश्यक पदार्थों के उत्पादन को बढ़ाने की तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है । एक समय एकदम एक चीज बाजार में ज्यादा आ जाती है, एक चीज का उत्पादन बढ़ जाता है, एक गायब हो जाती है । दूसरे वर्ष दूसरी चीज गायब हो जाती है । पहले चीनी गायब हो गई, फिर गेहूं की बहार हो गई, फिर चावल गायब हो गया, अगली बार गेहूं गायब हो गया । इस तरहसे हमजब अभाव होता है तब उसके लिए हाथ पांव मारते हैं । पहले से आवश्यकता के अनुरुप सुनियोजित ढंग पर नियोजन नहीं करते हैं । कितनी आवश्यकता होगी उसको देख कर उसके अनुरुप नियोजन नहीं करते हैं और जब अभाव हो जाता है तब कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ गयी । (व्यवधान) इस प्रकार से आज असंतुलित नियोजन और असंतुलित कार्यक्रम चल

[श्री दौलत राम सारण]

रहे हैं । न तो सरकार के पास कोई कृषि नीति है और न ही कोई भूमि नीति है । भूमि-सुधार की बात कह कर ये भूमि को बिगाड़ने में लगे हुए हैं । भूमि टूकड़ों में बटती जा रही है । दूसरी ओर जो वास्तविक कास्तकार हैं उनको बेदखल किया जा रहा है । और जो काश्तकार नहीं हैं, जो गैर-पेशा हैं वे फार्मों के मालिक बनते जा रहे हैं । जिनके बाप-दादाओं ने कभी खेती नहीं की, वे आज फार्मी के मालिक हैं । इन्दिरा जी फार्म की मालिक हैं । जिनके बाप-दादाओं ने अपना खून-पसीना बहा-कर हमेशा खेती की वे आज खेत से बेदखल किए जा रहे हैं । वे लोग आज भूमिहीन मजदूर बनते जा रहे हैं । दूसरी ओर सरकार ने सीलिंग का एलान किया लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है । शहरों में सम्पत्ति पर कोई भी सीलिंग नहीं है । अरबों रुपए के कारखाने लगाए जा रहे हैं और वह भी सरकार के पैसे से । उनको व्याज में छूट तथा तमाम अन्य प्रकार के कन्सेशन्स दिए जा रहे हैं । उनके द्वारा कमाए गए मुजाफे पर भी कोई कन्ट्रोल नहीं है । एक बेचारा किसान ही है जिसको कोई भी संरक्षण नहीं है । किसान को लूट से बचाने के लिए तथा व्याज और ऋण में उसको राहत देने के लिए कोई भी कार्यक्रम नहीं है । चूंकि सरकार की कोई सही और संतुलित कृषिनीति नहीं है इसीलिये कृषि क्षेत्र में असंतोष है और अभाव है ।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि सही ढंग से सही कृषि नीतियों को अप-नाया जाए ताकि खेती करने वाले पनप सकें और उनकी लूट बन्द हो, उनका शोषण बन्द हो तथा बिचौलियों से उनकी रक्षा हो सके । साथ ही साथ किसान को उसकी पैदावार की पूरी कीमत भी दी जाए । समर्थन और समता मूल्यों में संगति बैठाई जाए । आज औद्योगिक क्षेत्रों में मूल्य बढ़ते जा रहे हैं लेकिन कृषि क्षेत्र में किसान की पैदावार के दाम उस अनुपात में नहीं बढ़ रहे हैं । मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि वह समता मूल्यों की तरफ ध्यान दे और समथन मूल्य भी उसी हिसाब से निश्चित करे ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

SHRI G. NARSIMHA REDDY (Adilabad): Mr. Chairman, Sir, many of our colleagues have spoken sufficiently in detail on all the subjects of the Ministry of Agriculture. I would like to speak only on Forestry, a part of this Ministry. Since the last few years in our country many scientists and planners and even common people have started realising that the forests are gradually vanishing in our country and it is very necessary to take immediate steps to protect the forests and grow more. For this, I would like to congratulate all those scientists, planners and common people who have rightly drawn the attention of the Government and the people of this country regarding the immediate requirement of protecting the forests. I also thank the Press for sufficiently bringing out this problem and focussing attention.

MR. CHAIRMAN: Why do you not thank the Minister concerned?

SHRI G. NARASIMHA REDDY: That I will do after he takes action. So far action has not been taken. That is my plea. As the time is short, I will be quick, as many people are eargerly waiting to speak.

This subject I would like to deal in four points:

1. What was the situation of forests regarding the area, etc., about a few years back?

2. What is the present situation of forests?

3. Why has this situation come about? What are its reasons and who are responsible for this?

4. Lastly, what measures are to be taken immediately to save the forest and ecological balance.

Now, I will elaborate the first point. First, I would quote certain statistics from 'Indian Forests 1980' regarding the situation prevalent as on 1976:

The total area of forests is 74.74 million hectares, which is 22.7 per cent of our total land. This is divided into different parts i.e., reserved forest, which is 38.97 million hectares and which forms 52.1 per cent of the total reserved area for the forests. The second is protected forests, which is 23.19 mililon hectares. It comes to 31.0 per cent. The third is unclassed—not classified—which is 12.58 million hectares. It comes to 16.9 per cent.

The second one would be agriculture. The total cultivable land is 154 million hectares, which comes to 47.0 per cent. The other cultivated land is 43.1 million hectares, which comes to 13.1 per cent. Land under non-agriculture use is 17.2 million hectares, which comes to 5.3 per cent. Barren and uncultivable land is 39.1 million hectares, which comes to 11.9 per cent.

As per these statistics, per capita forest area works out to 0.11 hectares, which is extremely low, almost lowest in the world. If we compare with world figures, our forest area constitutes 1.85 per cent of the world forest area, whereas our population is 15.64 per cent of the world population.

It was suggested in our National Forest Policy some time back that 33.33 per cent of the entire area in the country should be covered with forests.

Now, I come to the present situation of the forests. During the last three decades, instead of increasing the forest area which was 22.7 per cent and which ought to have increased to 33.33 per cent, due to increase in population and pressure on land and increase in demand of forest produce from the industry-side, gradually the State Governments have started felling forests indiscriminately I would use that word because ultimately, what has happened is this. Within a short span, almost 4.3 million hectares of our forest area, which was supposed to be reserved for forests, was converted into use for non-forest purposes. It was at this juncture that our hon. Prime Minister has recognised the importance of forests and foreseen the danger of the land reserved for forests being converted into other use. That is why, last year, an ordinance was issued, an Act was passed later, called Forest Conservation Act, 1980, prohibiting use of the land, which was reserved for the forest area, for any other purpose than forests.

The most alarming situation today is that our Forest Department have failed miserably to tell the Government and the Nation how much forests they have. They are only quoting geographical statistics saying that we have reserved this much of land for forests. We are not only interested in knowing how much land you have reserved for forests but also how much forests you have in this country.

Here I would like to point out that I could not get information from anywhere, even from the Parliament Library, about the total area covered by forests in this country, either today, last year or three years back. I come from a district, which was supposed to have 40 per cent of forests. Of course, at present we do not have that much. From my little experience of Maharashtra, Madhya Pradesh and Andhra Pradesh, which comprises 50 per cent of the total area reserved for forests, I can say that we do not have any forests in this area. Our villagers, our industrialists and all other people have used them and now we do not have any forests.

Apart from that, even in the reserved forests, I am sure that a minimum of 10 to 15 per cent we have used up. So, if we statistically work out, the

[Shri G Narasimha Reddy]

areas covered by forests in the country would not be more than 9 to 10 per cent, I would be sorry to say. While our national policy says that we must have 33-1/3 per cent of the total area under forests, day by day the situatin is deteriorating from bad to worse.

At this point, I would like to say that the area which was reserved for forest purposes was 44.84 million hectares and 77.4 million hectares without forests. For many years even the area which is reserved for forests is not being put to any use. not even for agriculture. What is the result? Since we have to much of rains, if the land is not used, erosion takes place. So, gradually we have come to a situation where out of 44.84 million hectares most of the land has become barren and uncultivable. Already 11.1 per cent of the land is barren. So, in my opinion, according to a rough estimate, about 24 per cent of our geographical area declared as forest is barren and unfit for any use. Therefore, apart from losing forests, we are losing 24 per cent of our geographical area, which we are not able to use. This is a very alarming situation, to which Government should wake up.

Why has the situation come to such a pass? What are the reasons? Who are responsible for it? In the 19th century, when people realised the utility of the forests, for furniture and other purposes, they started felling trees. Government have realised the importance and the danger of their becoming extinct, if they are not reserved. In 1865 they took the initiative passed the first Indian Forest Act to control the indiscriminate feelíng. It was not having the desired effect of controlling it. So, in 1894 they passed the National Forest Policy which emphasized demarcation, reservation and conservation of forests. Yet, the area under forests was getting depleted rapidly. Therefore, n 1952, when our party came to power, we emphasized on environmental protection as the function of forestry and suggested 33-1/3 per cent of the areas under forests I would like you to make a note of this. Here, they say that 33.33 per cent of the country should be retained under forest cover. By quoting all this, I would only like to draw your kind attention to the fact that in 1865, i.e. 117 years back, the people at that time and the then Government also, realised the importance of the danger. Now, in 1982 what has happened? The whole forest is almost finished. We have landed in that dangerous situation today. In support of this....

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI G. NARASIMHA REDDY: Sir let me take five minutes. I am not going to speak on any political things.

MR. CHAIRMAN: According to your own submission you have to make one more point. So, come to the point and finish it.

SHRI G. NARASIMHA REDDY: What are the main reasons? I would say, the main reason of failure of all the previous governments is that forests were traditionally looked upon by all the previous governments as a source of revenue rather than as a sector needing investment. All these years the State Governments have exploited the forests indiscriminately only for earning revenue. I would like to prove what I am saying.

As per NCA Report, para IX, 1976, they have given the estimated requirement of the industrial wood and fuel wood. That is, in 1980 they wanted 210.9 million cubic metres while they exploited much more. In 1985 their requirement is 237.1 million cb. metres and in 2000 they need 289.5 million cb. metres. This clearly indicates that the area of the forests is coming down much more. As I said, the Government is using the forests for earning revenue and they are not making any substanthial investments on them. I would like to quote certain statistics to prove this.

MR. CHAIRMAN: You may conclude now. You have taken more time.

SHRI G. NARASIMHA REDDDY: Our hon. Minister will agree....

MR. CHAIRMAN: There are so many speakers.

SHRI G. NARSIMHA REDDY: You allow me to speak. Within the time you interrupted I would have finished.

MR. CHAIRMAN: I have allowed you more than sufficient time.

SHRI G. NARSIMHA REDDY: I would have made one point by this time.

MR. CHAIRMAN: Do you know how much time you have consumed?

SHRI G. NARSIMHA REDDY: I have taken 10 minutes.

MR. CHAIRMAN: No, you began at 2.26 p m.

SHRI G. NARSIMHA REDDY: Sir, from 1971 onwards our Government have been exporting timber and from 1971 to 1977, for six years, you will be surprised to know that we have exported timber worth Rs. 3309.2 million. There is no necessity of exporting. So, this only proves that our Government is using the forests for revenue purposes.

Another point is that in all the Five-year Plans put together we have invested only Rs. 3,400 million, which is almost equal to our earnings from export. For example, the total revenue from forests in 1976 was Rs. 3,444.75 million while the normal expenditure was Rs. 1,446.09 million and the net revenue was Rs. 1998.66 million. In that year the Government has invested in the developmental and plan activities Rs. 443.28 million, that is, not more than 20 per cent of the revenue.

I am of the opinion that we have the right to use timber for all purposes, but morally we are bound because the previous generations have handed over the forests to us and it is the moral duty of the Government and people to see that a minimum of 33.3 per cent of the forests is also handed over to the future generations.

So, Sir.....

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI G. NARSIMHA REDDY: No, I am not going to sit. I am going to make points unless you throw me out.

MR. CHAIRMAN: What is this.

SHRI G. NARSIMHA REDDY: It is very important.

MR. CHAIRMAN: It is too much. I have requested you time and again. Is it proper that you say 'I am not going to sit'?

SHRI G. NARSIMHA REDDY: If you order me I will have to sit.

MR. CHAIRMAN: A senior Member like you should not say like this.

SHRI G. NARSIMHA REDDY: All right. I withdraw it. Please allow me. With folded hands....

MR. CHAIRMAN: Kindly finished. Do not speak like that.

SHRI G. NARSIMHA REDDY: If you stand, I will sit down. Please....

MR. CHAIRMAN: Please co-operate.

SHRI G. NARSIMHA REDDY: At least in the interest of forest you allow me to speak.

MR. CHAIRMAN: I am very much interested in forest.

SHRI G. NARSIMHA REDDY: There is a question, who is responsible for destruction? I would like to say that this is a controvercial point. People have been saying that the villagers who are staying in the area are responsible for destruction of the forest. Here I would like to state to the House and the people that it is not....

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI G. NARSIMHA REDDY: If you stand, I will have to sit down.

MR. CHAIRMAN: Nobody can check you. Time and again I have requested you to finish.

SHRI G. NARSIMHA REDDY: I will conclude. With your permission I will conclude.

I would only say the villagers who stay in the forest area, they change the forest area because they use firewood and construct huts. More than that it is not they who are responsible for destruction of the forest. As I have already said—the planning was

[Shri G. Narsimha Reddy]

wrong. The State Governments are responsible.

The following steps should be taken immediately:

1. We should stop exporting the timber.

2. For the wood-based industries which require more than 15 million cu. metre, it must be made compulsory for all big and large scale industries in this country to grow their own timber, their own raw material for which Government should allot land.

Here some of the Forest Officers feel, it is only they who can run the show. It is not so. The main issue is how to replace the productivity which is .2 cu. metre per hectare and de-forested area, with various growing plants at a rate which will keep pace with rising demands of the industrial wood, fuel wood and other timber requirements.

3. How to protect the remaining forest from indiscriminate destruction by the State Government and others and how to preserve the environment.

Lastly I would request the hon. Minister to come up with the fresh Bill or include in the coming Bill the necessity of prohibiting the revenues earned from the forest for utilisation for purposes other than forestry. I mean to say whatever the revenue the Government is getting today from the forest, they must plough back all the revenues into the forest area to create more forests and to protect the forest till the time we reach 33.3 per cent.

MR. CHAIRMAN: I have a long experience but it is a peculiar attitude to assert 'I would not sit'. In a situation like this, how can anybody control the proceedings?

Shri R. L. Bhatia.

SHRI R. L. BHATIA (Amritsar): I rise to support the Demands for Grants under the control of the Ministry of Agriculture.

Our friend on the opposite side mentioned that last year the Government of India imported 15 million tonnes of wheat. It is incorrect. I want to correct him through you. It was only 15 lakh tonnes. That means 1.5 million tonnes.

Similarly, the hon. Member Shri Saran tried to establish that foodgrains in this country are decreasing and the Government of India is doing nothing in this matter. I would like to tell him that if he would have read the report of the Ministry, perhaps he might not have said it. In the year 1976-77, the total food grains produced in this country was 111 million tonnes. Last year, it was 132 million tonnes and this year it is likely to touch 130 million tonnes. It is all due to the efforts of the Government of India by providing better seeds and better irrigation facilities that we have been able to produce more. If I read the figures for the last five years, he will be convinced.

Rice production in the year 1977 was only 42 million tonnes. But last year in 1981, it was 53 million tonnes. Similarly, wheat in 1977 was only 29 million tonnes but last year, in 1981, it was 36.46 million tonnes. This shows that the Government of India is doing its best to increase the foodgrains in this country and it is only due to the efforts of this Government, we are having more and more production. I must also mention here that we are increasing production of sugar as well as cootton, ut we are lacking in the production of pulses. In 1977, it was 11.36 million tonnes. But last year, it has gone down to 11 million tonnes. So, no effort has been made to produce more pulses. I will draw the attention of the Minister to this side that pulses are very important foodgrains in this country. Since we are having increased production in all the areas, why do we lag behind in the production of pulses? I would like to draw his attention to this side.

In order to meet the demand of 68 crores of people of this country, the

Minister has chartered a three-tier policy—the policy of procurement, the policy of storage and the policy of distribution. So far as the policy of procurement is concerned, I am surprised why procurement of all the surplus foodgrains is not taken care off? Coming to wheat, you will see that last year out of 36 million tonnes of foodgrains, only 6.59 million tonnes was procured. Normally, 1/3rd of the total foodgrains arriving in the market is procured as surplus and 2/3rd is left for the farmers for their consumption and seed purposes. Therefore, 1/3rd of the foodgrains comes to 12 million tonnes. But only 6 million tonnes was procured. I fail to understand why another 6 million tonnes has been left to the traders, blackmarketeers and hoarders, who always take advantage of the situation. They hoard the grains and release only when there are sufficient profits. In this country, drought and flood are common features. It is, in this situation, that we find that blackmarketeers and hoarders take advantage. Therefore, my suggestion is that the Government must take over another 6 million tonnes which is market surplus and build their reserve.

It has been seen that at the time of arrival of crops in the market, the price of food grains is the lowest and it goes on increasing in the lean months. If you see the figures for the last two years, the farmers are right in criticising the policy of the Government. At the time of arrival of crops they were paid Rs. 130 per quintal. In the lean months, the price of the wheat has gone to Rs. 160 or Rs. 170. Naturally, they are aggrieved. If you procure all the surplus foodgrains coming to the market, I am sure there will be balance in price.

There is also another important point which I would like to make. The procurement policy is not uniform. You call it, national policy. In fact, I will prove, it is only a policy in Punjab and Haryana. Other States are not contributing to the procurement policy. In U.P. which is the biggest State in India, in the year 1980-81, they procured only 5 lakh tonnes and in the year 1981-82, they also procured only 5 lakh tonnes. In Madhya Pradesh which is another big State, in 1980-81, it was negative procurement and in 1981-82, it was only 1.64 million tonnes. So, I would like to ask the hon. Minister if he could explain to us why there is a discrimination in the policy of procurement why procurement is taking place in Punjab and Haryana only and why not in other States. This has led to the traders and other people taking advantage of the situation.

Of the total 6 million tonnes of foodgrains procured all over India. I am proud to say that Punjab contributed 3.76 million tonnes of foodgrains to the reserve of the Centre. Why is it so? It is because there is an efficient Government; there is a good Government which believes that they must help the Centre. It is because of the fact that we have got the most efficient system of procurement. Why this system of procurement is not there in other States? The Central Government must gear it up. I know, the hon. Minister will say that the State agencies are purchasing the foodgrains. What about the FCI which they have created? Wherever there is any State Government which fails in procuring foodgrains, the FCI is there to fill the gap I would, therefore, like that he must gear up the administration for better procurement of foodgrains.

Now, I come to rice. It is the same story. Out of 53 million tonnes of rice that was produced last year, they procured only 6 million tonnes. Just imagine how low it is. In U.P. again the story is the same. They purchased only 5 lakh tonnes. In Madhya Pradesh, they procured 3 lakh tonnes. But in the case of a small State of Punjab which consists of only 12 districts, it gave 30 lakh tonnes of rice to the Centre which is almost 50 per cent of the total procurement all over India, in all the States. Therefore, I would like to request the hon. Minister not to make this discrimination between the State which are pro-

[Shri R. L. Bhatia]

curing and he is giving a sort of lease to others which are procuring and which are selling at a higher rate.

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT AND CIVIL SUPPLIES (RAO VIRENDRA SINGH): Shall we stop procuring in Punjab?

SHRI R. L. BHATIA: I do not say that. I am coming to my proposals. I would like you to give a categorical reply.

Regarding storage, that is indeed a very important thing and it brings stability in the prices as well as ensures supplies to our price shops. Some time ago, a technical group suggested that 12 million tonnes should be our buffer stock. Now, in the Sixth Five Year Plan, 15 million tonnes has been suggested. I think, it is too low. In other countries, what we find is that the total consumption of a year is kept as buffer stock. It is the same in America, it is the same in the USSR. I would request the hon. Minister to follow that policy and at least 20 million tonnes of foodgrains should be kept in the central pool after defraying and making supplies to the fair shops.

There are 2.98 lakh fair price shops for the distribution of our foodgrains. Last year, we distributed 13 million tonnes of foodgrains and after we distributed 13 million tonnes of food grains, the result was that out stock was as low as, 11 million tonnes. That is probably why they imported foograins. I would therefore, suggest that the buffer stock should be increased by having more procurement. It will help us in all the way. Because India is a poor country and there are droughts and floods, in the time of need this big buffer stock will be very useful to us.

As this stage, I would say that foodgrains is a very important thing so far as the world politics is concerned.

15 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

Many countries are demanding foodgrains and some people who are having it are not giving. It is an ideal opportunity for us to increase our production. For a country like India which has got such a large area, which has got such a big population and where so many millions of hands are idle, we can certainly increase our foodgrains production to 150 million tonnes. The surplus foodgrains we can export. India is facing a foreign exchange situation at this time on account of oil prices and we can certainly make it by exporting foodgrains. Therefore, it is the responsibility of this Ministry to provide more irrigation, to provide more facilities and raise production to at least 150 million tonnes.

Now I come to Punjab. Punjab, as I stated, has contributed 50 per cent, rather more than that, to the Central reserves. The Minister asked me, 'Should we not procure?' I say, why don't you pay bonus to the Punjab farmer who has shown hard labour, who has obeyed your order and who has filled the coffers of the Central Government. Why not pay bonus to the Punjab farmers? If you pay bonus, I tell you, they will produce more and you are yourself a farmer. We look to you that you will come to the rescue of the farmers of India. You have raised the price to Rs. 142 per quintal which is too meagre. The infrastructure is so dear. Now you see the prices of fertilisers and the prices of every other input have gone up. So instead of paying Rs. 142 which was recommended by the Commission, we expected from you—because you know the difficulties of the farmer, you know in what difficult circumstances he is growing foodgrains—that you should have at least paid Rs. 150 per quintal and I demand from you that the price of wheat should be declared not Rs. 142 but Rs. 150 minimum

MR. DEPUTY SPEAKER: Mr. Bhatia—I am helping you. In this productivity year your suggestion, if accepted by the Government, will enthuse the farmers very well, especially in Punjab.

SHRI R. L. BHATIA: In Punjab more and more people have gone to sugar cane cultivation and the cane is now standing in the field and the factories are closing. It is a great national loss. I will request you to grant at least 6 sugar cane factory licences to Punjab to fulfil its objectives.

Lastly I request you and I strongly demand bonus for the farmers of the country and especially to the farmer of Punjab and those States which have fulfilled their targets of procurement. At least I would expect from you that you will congratulate the Punjab Government which has done so efficiently that they are contributing more than 50 per cent to the central reserve.

*SHRI E. K. IMBICHIBAVA (Calicut): Mr. Deputy Speaker, Sir, while the House is discussing the demands relating to the Ministry of Agriculture, I wish to bring to the attention of the Government certain very important problems. India is essentially an agricultural country. Today there is wide spread discontent among the farmers in our country. The main problem is related to the question of remunerative prices for agricultural produce. This problem is raging like a storm in all the States. I warn this Government that if they fail to take timely steps to redress the grievances of the farming community before long they will find themselves uprooted by the storm of the farmers protest. I would ask the Government as to why is it that they are not able to pay remunerative prices to the farmers. We have to seriously ponder over it. This Government has not been able to formulate a sensible national policy in regard to the prices of essential consumer goods. They are pursuing a policy of expropriating the farmers by offering a pittance for their produce and at the same time giving all encouragements to the monopolists so as to enable them to grow and fatten themselves. Succumbing to their pressure the Government is pursuing such policies which are systematically destroying the farmers. I will cite just one example to prove my contention. It is well known that the main agricultural crop of Kerala is coconut. Kerala accounts for 70 per cent of the total production of coconut in the country. There was a time when coconut prices were ruling rather high and this encouraged the farmes to cultivate coconut extensively. But the import policy of the Central Government has broken the backbone of Kerala's coconut growers. A very wrong step was taken by the Government in importing coconut oil. We met and requested the Central Cabinet Ministers who are concerned with it and even the Prime Minister to desist from the import of coconut oil. Every time we met them they assured us that import was not being allowed. But we had occasions to see with our own eyes imported coconut oil being unloaded in Bombay and Cochin ports. Sir, do you know to what extent this import has brought down the price of coconut in the domestic market? The price came down by Rs. 500/- per thousand coconut. As a result of this the farmers of Kerala lost as much as Rs. 1,500 crores. When the farmers who produce wealth for the country are put to such huge loss what will happen to the country Who are these farmers? They are not Tatas and Birlas. 60 per cent of them are those who own 10 or 20 cents or may be half a hectare of land. It is they who are put to such hardship by the wrong policies being pursued by the Goernment. Permission for import is given and import agreements are signed. I want to remind this House that in these imports all the rules regarding import duty are circumvented. This problem is not confined to coconut alone. Take the case of cocoa. The Government of India itself had encouraged the farmers to go in for cocoa cultivation. Who are the buyers of cocoa in our country?

*The original speech was delivered in Malayalam.

[Shri E. K. Imbichibava]

Cadboury, a multi-national company is the major buyer. They have got their own factories in Philipines and some other places outside. They made all efforts to reduce the price of cocoa. Scumbing to their pressure the Government of India resorted to import of cocoa and thus caused heavy loss running into crores of rupees to the cocoa growers. Same is the case about rubber. (*Interruptions*) Thus if we take each and every major agricultural and commercial crop produced in our country we would find that the policies of the Government have brought about utter ruin in the agricultural sector. The result is that there is seething discontent in this sector. The most estounding thing is that they are even going to import pepper. I cannot understand how you are going to ensure the economic development of the country while ignoring the fact that agriculture is the foundation of all economic development of a country like India. It is the totally wrong, narrow minded and anti-national policy of systematically destroying the vast agaricultural sector and pampering a few monopoly industrial houses that has resulted in the present mess. I would only request the Goernment that the sooner it abandons that policy the better for the country.

Another point I want to deal with the fisheries department¶ Kerala's marine products earn us substantial foreign exchange. It must interest us to find what is happening in the sector. During its 21-months tenure the previous Nayanar Government of Kerala had done a lot of good work in this sector. That Government had formed 124 fishermen cooperative socities in the coastal area of Kerala and thus made earnest efforts to help the fishermen. All necessary arrangements were made to put the societies on an even keel. But when the "casting vote Ministry" came to power all these arrangements were subverted and even the officials who were appointed by the previous Government for looking after the above said societies were withdrawn. Not only that, the previous Government by Mr. Nayanar formulated a scheme of insurance where-under if a fisherman losses his life while fishing in the sea, his family members would get Rs. 10,000. Now it is said that this scheme will be substituted by some other arrangement which will be so dilatory and time consuming that the intended beneficiaries will not get any benefit in time. Sir, you can very well imagine the miseries of fishermen's famillies when their bread earning members die. Similar arrangements were also made by the previous Government to develop fishing harbours at Beypore, Kasargode, Azhikkal, Ponnani Kodungallur etc. In 1968, the Indo-Pole Company had made a detailed study of the developmental problems of these harbours and submitted its report. But what happend to all that? Sir, it is very essential to develop these ports. In this contact I would draw your attention to another equally important port which has to be developed. That is Midnapur. Recently when I visited that place the fishermen there impressed upon me the urgent necessary of it harbour there. I would request to consider that also.

I would now say a word or two about the Food Corporation of India. We must know how this Corporation taking a wrong attitude in regard to the rights of the workers who are working directly under it or in some way or the other are connected with it. For exemple in a place called Kuttipuram in the State of Kerala, contributions towards provident fund

were collected by the Corporation from the workers who are engaged in loading and unloading. But even after many years these amounts have not been deposited. A case came up before the P.F. Commissioner and be ordered for depositing . It is the hard order for depositing of the PF amount immidiately. It is the hard earned money of the workers and the Corporation should not detain it. I would request the hon. Minister to issue immediate instructions to the Corporation to deposit these amounts to the workers with all the interest. What right has this Government got to proudly claim that ours is a welfare State when they cannot ensure atleast a minimum of facilities to their own workers so as to enable them to live like human beings.

Sir, many Central Ministers including hon. Shri Stephen visit Kerala. One would expect them to look into the grievances of the public on major issue concerning the interest of the State. But instead of taking such an approach they come there only to create confusion. The people of Kerala are suffering today mainly because of the negative and unhelpful stand taken by them on public issues. Whether it is the question of rubber, tea, cocoa, or coconut, their wrong policies have totally destroyed the economy of Kerala. Therefore, I would request that the Central Government should make a total break with the wrong policies that they have been pursuing so far and come to the help of the people Kerala. With these words I conclude.

श्री सतीश प्रसाद सिंह (खगरिया) : उपाध्यक्ष, महोदय, कृषि, के क्षेत्र में हमने बहुत तरक्की की है । कृषि, की उपज में भी बहुत बढ़ौतरी हुई है । देश के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छा काम किया है । इसके लिए वे प्रशंसा के पात्र हैं । गौर से देखने पर हमको पता चलता है कि कृषि अनुसंधान के कार्यों में तथा कृषि शिक्षा के कार्यक्रम में हम जितना आगे बढ़ते हैं, उस हिसाब से कृषि प्रसार में हम आगे नहीं बढ़े हैं । वैज्ञानिकों का मत है कि किसान 25–30 प्रतिशत कृषि सम्बन्धी आधुनिक तकनीक को जान पाए हैं । इस हिसाब से हमारे देश में जो दो-तीन गुना कृषि की उपज बढ़ सकती है वह नहीं बढ़ पाई है । किसानों के बीच में जो कृषि सम्बन्धी तकनीक का प्रसार होना चाहिए वह नहीं हो सका है । मैं खास तौर से मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो हमारे देश में कृषि सम्बन्धी अनुसंधान कार्य हुए हैं तथा जो शिक्षा दी गई है उसका प्रसार हर जगह होना चाहिए ताकि हमारी उपज दो-तीन गुना बढ़ सके ।

दूसरी बात यह है कि 1951 से देश में सामुदायिक विकास योजना लागू हुई थी और उसके लागू होने से देश में कुछ काम भी हुआ । जिस ढग से काम हो रहा है, उस में कुछ शिथिलता आई है । हम ने जन सेवकों को कृषि का प्रशिक्षण दिया था और वे जो कार्य कर रहे थे उस समय सरकार के द्वारा यह अनाऊन्स किया गया था कि ये जो जन सेवक हैं उन की तरक्की होगी और कृषि विभाग में वे अच्छी से अच्छी जगहों पर जा सकते हैं । इस लिए उस समय उन के मन में अच्छा काम करने की भावना बहुत ज्यादा थी और शुरू के वर्षों में उन्होंने काम भी अच्छा किया लेकिन उसके बाद काम में शिथिलता बढ़ती जा रही है और उसका कारण यह है कि उन के प्रोमोशन की कोई गुंजाइश नहीं है । वे जन सेवक ही वर्षों तक बने रहते हैं जिसकी वजह से जो उत्साह उनके मन में पहले था, वह अब नहीं रह गया है और काम में ढिलाई बढ़ गई है ।

एक बात की तरफ़ और ध्यान दिलाना चाहूंगा कि कृषि, के जो कार्यकर्ता गांवों में काम करते हैं, उन्हें तनख्वाह कम मिलती है मुकाबले उन लोगों के जो शहरों में काम करते हैं । शहरों में जो काम करते हैं

[श्री सतीश प्रसाद सिंह]

उन की पे एन्ड एलाऊन्सेज ज्यादा हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि जो गांवों में काम करने वाले हैं, उन को भी उतनी पे और एलाऊन्सेज़ मिलने चाहिए जितना कि शहर में रहने वालों को मिलते हैं ताकि गांवों में जाने के लिए लोग तैयार रहें। ऐसा देखा जाता है कि अक्सर गांवों में लोग अपनी पोस्टिंग नहीं कराना चाहते और अगर पोस्टिंग हो भी जाती है, तो फ़िर वहां मन से काम नहीं करते और पैरवी करा कर अपनी बदली कराना चाहते हैं। ऐसी हालत में गांवों का जो विकास होना चाहिए, वह अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए इस तरफ़ ध्यान देना चाहिए कि गांवों में जो काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, उन का वेतन ज्यादा होना चाहिए उनके कम्पेरीजन में जो शहरों में काम करते हैं और जिन को सब सुविधाएं प्राप्त हैं। उनको जो एलाऊन्सेज़ मिलते हैं, वही गांवों में काम करने वालों को मिलते हैं क्योंकि गांवों में उन लोगों को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनको वहां पर रहने के लिए मकान नहीं मिलता है और दूसरी बहुत सी परेशानियां हैं। ऐसी हालत में उन का ज्यादा एलाऊन्सेज मिलने चाहिए।

जहां तक ट्रेनिंग का सवाल है, जो अनुसंधान हम करते हैं, साइंटिस्ट्स जो नये बीज निकालते हैं और जो खेतों के नये नये तरीके निकाले जाते हैं, उन के बारे में किसानों को प्रशिक्षण देना चाहिए। बीच-बीच में किसानों को लगातार प्रशिक्षण मिलते रहना चाहिए ताकि वे नई-नई चीजों से अवगत रहें और उस के अनुसार खेती करें, क्योंकि आजकल खेती कोई साधारण बात नहीं रह गई है और अब यह एक महगा उद्योग हो गया है। बड़े किसान तो किसी तरह से अपना काम चला लेते हैं लेकिन जो छोटे किसान हैं, वे इस का रिस्क लेने को तैयार नहीं कि वे कोई चीज़ करें और उस का रिटर्न उन को न मिले। ऐसी हालत में प्रशिक्षण बराबर मिलना चाहिए और जो नये-नये अनुसंधान हों, जो नई चीजें निकलें और जो नये तरीके निकले, उन से उनको अवगत कराते रहना चाहिए।

1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग ने एक रिपोर्ट दी थी कि जो कृषि विज्ञान केन्द्र हैं, छटी पंचवर्षीय योजना तक प्रत्येक जिले में दो केन्द्र ऐसे खुलने चाहिए और 2000 ई० तक एक जिले में ऐसे तीन-तीन केन्द्र खुलने चाहिए ताकि ज्यादा अनुसंधान हो सके लेकिन अभी जो कृषि विज्ञान केन्द्र खुले हैं, वे 30–35 ही खुले हैं और किसान प्रशिक्षण केन्द्र जो है, उनकी संख्या सारे मुल्क में 150 थी जो अब घट कर 141 रह गई है। बढ़ने की बजाए, वे घट गये हैं। इस तरह से किसानों को ट्रेनिंग देने की जो रुचि बढ़नी चाहिए थी, वह कम हो गई है। मेरी समझ में इस का एक मुख्य कारण यह है कि सेण्टर जो पैसा देती है, वह 50 परसैण्ट ही देती है और बाकी 50 परसेण्ट पैसा स्टेट्स को देना पड़ता है और स्टेट्स इतना इण्ट्रेस्ट नहीं ले रही हैं। कृषि जो है, वह एक राष्ट्रीय सवाल। इसलिए में मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो 50 परसेण्ट पैसा आप किसानों के प्रशिक्षण के लिए देते हैं और उतना ही पैसा स्टेट्स से लेते हैं, तो जिस समय बजट में स्टेट्स का पैसा आप एलोकेट करते हैं, उसी समय यह इयरमार्क कर देना चाहिए कि इतना पैसा इस प्रोग्राम के लिए है जैसा कि आई०सी०ए०आर० के लिए करते हैं। इस ढग से करने से यह जो आप की स्कीम है, इसमें आप पूर्ण रूप से सफ़ल होंगे। और किसानों को फ़ायदा होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो राष्ट्रीय खेती आयोग की अनुशसा है उस पर ध्यान दिया जाए और उसको बढ़ाया जाए।

छठी पचवर्षीय योजना में कम से कम चार सौ कृषि विज्ञान केन्द्र होने चाहिए

थे लेकिन अभी तक सारे देश में केवल 30–35 केन्द्र ही खुले हैं । यह भी अनुशंसा है कि दो हजार ईस्वी तक प्रत्येक जिले में कृषि विज्ञान केन्द्र की सख्या तीन और सारे देश में 1200 हो जानी चाहिए । इसी प्रकार आयोग की यह भी रिपोर्ट है कि किसान प्रशिक्षण केन्द्र सारे देश में खोले जाने चाहिएं । ये केन्द्र अभी तक 150 खोले गये थे लेकिन उनमें से भी अब 141 केन्द्र ही रह गये हैं । इसलिए मंत्री जी इस बात पर ध्यान दें और आयोग की रिपोर्ट में दी गई अनुशंसा पर कार्य करें ।

नार्थ ईस्टर्न जोन एक पहाड़ी एरिया है । उसमें आई० सी० ए० आर० ने बहुत सी स्कीम शुरू की हैं और अच्छी स्कीम शुरू की हैं । लेकिन वहां के लोग उनमें रुचि नहीं ले रहे हैं क्योंकि वहां सिचुएशन कुछ दूसरा सिचुएशन है जिससे वहां के रहने वालों को उनमें काफी दिक्कत होती है । वहां के लोगों को होर्टिकल्चर में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जिसमें कि वे बहुत तरक्की कर सकते हैं । इस तरफ भी मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए ।

एक बात की ओर मैं और इशारा करना चाहूंगा । हिन्दुस्तान में फार्म के काम में लगभग आधी औरतें काम करती हैं । इसलिए जहां भी शिक्षा और ट्रेनिंग देने का सवाल हो उसमें लेडीज के लिए 50 परसेंट नहीं तो जितना अधिक से अधिक हो सके उनके लिए रिजर्वेशन करना चाहिए ।

अभी जो हमारी देहात में शिक्षा चल रही है उस शिक्षा में एग्रीकल्चर के, कृषि के सम्बन्ध में कोई पढ़ाई नहीं होती है और जो लड़के मैट्रिक फेल कर जाते हैं या पास कर जाते हैं, उन्हें गांवों में ही रहना पड़ता है और उनमें कृषि के सम्बन्ध में रुचि उत्पन्न नहीं हो पाती है । मेरा सुझाव है कि देहातों के प्रत्येक हाई स्कूल में बी० एस–सी एग्रीकल्चर शिक्षक बहाल करने चाहिएं ताकि वे देहातों के विद्यार्थियों को बता सकें कि खेती के बारे में विज्ञान ने क्या क्या तरक्की की है और खेती में वें लोग किस तरह से तरक्की कर सकते हैं । इस तरह से अगर उनको नौकरी नहीं मिलेगी तो कृषि के सम्बन्ध में जानकारी होने से वे अपना कृषि का धंधा अच्छी तरह से कर सकेंगे और इससे हमारी कृषि भी आगे बढ़ेगी ।

सन् 1976–77 में इण्डो बल्गेरिया एग्रो इंडस्ट्रियल काम्पलेक्स खोले गए । एक बिहार में और एक कर्नाटक में खोला गया । यह काम्पलेक्स बहुत अच्छा है । इसमें वेजीटेबल और फ्रूट्स की मार्किटिंग, पैकिंग, प्रोसेसिंग का काम होना था । ऐसे काम्पलेक्स बल्गेरिया जैसे छोटे से देश में 170 हैं जब कि हमारे इतने बड़े देश में तो ये हजारों की संख्या में होने चाहिए थे । लेकिन ये जो काम्पलेक्स खुले थे इनका भी क्या हुआ, इसकी भी किसी को जानकारी नहीं हो सकी है । मंत्री जी इसकी तरफ भी ध्यान दें । यह एक बहुत अच्छी स्कीम है । इन काम्पलेक्स को चलाया जाना चाहिए और नये काम्पलेक्स खोलने चाहिए । मंत्री जी इस पर ध्यान दें और यह बताएं कि इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ।

मेरा क्षेत्र खगरिया एक ऐसा क्षेत्र है जो कोसी और गंगा के बीच में है । एक तरफ उसके कोसी है और दूसरी तरफ गंगा है । वहां बाढ़ का भी प्रकोप रहता है । इसके लिए कुछ इंतजाम भी किया गया है । वहां केले की खेती होती है, वहां मछली बहुत ज्यादा होती है और मक्का भी बहुत ज्यादा पैदा होती है । दूध भी काफी मात्रा में उपलब्ध होता है । अगर इन सब चीजों को वहां एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगाई जाएं तो वहां के लोगों को काफी फायदा हो सकता है । इसके सिवाय वहां के लोगों के पास कोई साधन नहीं हैं । इसके बारे में मैंने मंत्री जी को लिखा भी था और मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इसका

[श्री सतीश प्रसाद सिंह]

सर्वे कराएं और उस सर्वे को अनुशंसा के आधार पर वहां एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज खुलवाने की कोशिश करें ।

इतना कह कर मैं अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं ।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : उपाध्यक्ष जी यह बात सर्वमान्य है कि कृषि हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था की आज भी रीढ़ है और यदि हिन्दुस्तान में खेती और खेती करने वालों की हालत नहीं सुधरेगी तो यह देश गरीब रहेगा और इस देश में गरीबी बेरोजगारी और आर्थिक विषमता खत्म नहीं हो सकती । आज दुर्भाग्य की बात है कि 35 वर्ष की आजादी के बाद भी हमारे देश में किसानों की आर्थिक हालत सबसे ज्यादा खराब है । आज अगर हम बिल्कुल निष्पक्ष रूप से देखें तो किसान की हालत में ज्यादा सुधार नहीं हुआ है । भाटिया जी ने हरियाणा और पंजाब के किसानों की चर्चा की पर उनको भी मालूम है कि पंजाब और हरियाणा का किसान दूसरे प्रदेशों के किसानों की अपेक्षा ज्यादा उन्नत, ज्यादा अमीर और ज्यादा आधुनिक खेती करने वाला होने के बावजूद 90 फीसदी किसान कर्जे से दबा हुआ है । देश के विभिन्न भागों में किसान 90 फीसदी कर्जे से दबे हुए हैं । खास तौर से ऐसे किसान जिनके पास 2–3 एकड़ से कम जमीन है, उनकी हालत बिल्कुल एक खेतीहर मजदूर की श्रेणी के बराबर है । छोटे किसान और खेतीहर मजदूर दोनों की हालत बहुत खराब है ।

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : काम नहीं करना चाहते ।

श्री चन्द्रजीत यादव : काम करने के बावजूद, आप अगर पंजाब में जा कर देखें तो 90 फीसदी किसान कर्जे के बोझ से दबा हुआ है । काम करने वाला किसान ।

श्रीमन्, अभी जो कीमत दी जा रही है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि पिछले तीन वर्षों में खेती के इस्तेमाल में आने वाली वस्तुएं, जैसे—फर्टीलाइजर, डीजल, ट्रेक्टर, सीमेंट और दूसरे सामानों के दाम जिस रेट से बढ़े हैं, उसको अगर औसत निकाली जाए तो उस औसत से सरकार ने किसानों को न तो गन्ने की कीमत दी है और न गेहूं, चावल, सरसों, चने आदि की कीमत दी है । इसकी वजह से किसानों में गहरा असंतोष है । मेरी सब से बड़ी आलोचना यही है कि सरकार किसानों के साथ इन्साफ नहीं करती । जब तक किसान आंदोलन नहीं करता, लड़ने के लिए मजबूर नहीं हो जाता, तब तक उसको उचित दाम नहीं मिलता । पिछली बार गन्ने का दाम 13 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया था और जब सारे देश में किसानों ने आन्दोलन शुरू किया और जब आन्दोलन महाराष्ट्र और तमिलनाडु में शुरू हो गया तो तो उसके डर से फिर सरकार ने 20 रुपये प्रति क्विंटल कीमत दी, लेकिन यह कीमत उसको पहले दे दी जानी चाहिए थी । मुझे कृषि मंत्री महोदय एक भी उदाहरण दे दें इस देश में कारखाने के मालिक, उद्योग-पति कभी अपनी कीमत के लिए आन्दोलन करते हों, कभी वे भी अपने कारखाने बन्द करते हों ? उसके बिजली का दाम, मजदूरों की तनख्वाह, डीजल के दाम बढ़ने से उसका जो उत्पादन का रेट बढ़ता है, उस रेट से सरकार बिना किसी आन्दोलन के उसका मुनाफ़ा बढ़ा देती है, लेकिन एक किसान ऐसा है जो इस देश की रीढ़ होते हुए, जब तक लड़ता नहीं है और सरकार को मजबूर नहीं करता, तब तक सरकार उसके साथ न्याय नहीं करती । जो 142 रुपये गेहूं का दाम निर्धारित हुआ वह इस बात का सबूत है । बोने से पहले सरकार को दाम घोषित करने चाहिए ।

किसान के इस्तेमाल में आने वाली वस्तुओं के दाम 31 फीसदी से ज्यादा बढ़े हैं और उसका रेट बढ़ाया गया है 22 फीसदी के करीब। किसानों के साथ यह नाइंसाफी क्यों ? मैं यह बात कृषि मंत्री जी से पूछना चाहता हूं।

श्रीमन, इस देश में सिर्फ़ 25 फ़ीसदी गांव में बिजली पहुंची है और 80 फ़ीसदी गांव सड़कों से नहीं जुड़ पाए हैं। 90 फ़ीसदी गांव में अस्पताल नहीं हैं। गांवों में किसान रहते हैं। आज इस देश में 35–40 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं, उनमें से 90 फ़ीसदी आदमी गांव में रहते हैं। वे या तो खेती करते हैं या खेतीहर मजदूर हैं या छोटे दस्तकार हैं। जब तक हम गांव में रहने वालों की हालत नहीं सुधारेंगे, उनकी आर्थिक स्थिति को नहीं सुधारेंगे, तब तक हिन्दुस्तान एक गरीब और पिछड़ा हुआ देश बना रहेगा—इस बात को सरकार को मानना चाहिए। आज उद्योगों और कारखानों में जो सामान तैयार होता है उसके दामों के बारे में सरकार की एक नीति है और खेत में पैदा होने वाले सामान के बारे में दूसरी नीति है। मेरी मांग है कि एग्रिकलचर प्राइस कमीशन को समाप्त कर दिया जाए और राष्ट्रीय प्राइस एण्ड प्राफ़िट कमीशन बनाया जाना चाहिए और वह एक तरफ़ से, एकरूपता कीमतों के अन्दर लाएं फ़िर चाहे वह कारखानों का सामान हो, उद्योगों द्वारा तैयार किया गया सामान हो या खेती में पैदा किया गया सामान हो, और एक ही तरह का मुनाफ़ा, एक ही तरह की कीमत लागत मूल्य जोड़ कर तय करे और इन सभी को वह मिले।

मेरी यह भी मांग है कि भूमि सुधारों को सख्ती से लागू किया जाए। आज हदबन्दी नहीं हो रही है। आज भी देश में लाखों किसान हैं जिन के पास सैंकड़ों और हजारों एकड़ जमीन बेकार पड़ी हुई है जबकि दूसरे किसानों की हालत खराब है। जापान में 99 परसेंट किसानों के पास दो एकड़ से भी कम भूमि है लेकिन हम से वे छः गुना पैदा करते हैं और मेहनत करते हैं। वे इटेंसिव खेती करते हैं। छः गुना ज्यादा वे पैदा करते हैं। हमारे यहां भी किसानों को सुविधाएं दी जानी चाहिये।

आज भी पंद्रह करोड़ से ज्यादा रुपया किसानों का चीनी मिलों के ऊपर बकाया है। अगर यही हालत रहेगी तो दो सौ करोड़ से ज्यादा रुपया किसानों का चीनी मिलों की तरफ़ बकाया हो जाएगा जो वे नहीं दे पाएंगे। अगर यही नीति सरकार की चलती रही और किसान को गन्ने के दाम नहीं मिले और वे बकाया रहते रहे तो अगले साल मैं वार्न करता हूं कि सरकार को चीनी का आयात करने पर मजबूर होना पड़ जाएगा। आज कपास की कीमत किसान को पूरी नहीं मिल रही है। यही हालत रही तो आपको 1983 में कपास का भी आयात करना पड़ेगा। मैं अपना अनुभव बताता हूं। जब किसान को उसकी पैदावार के उचित दाम नहीं मिलते हैं, दाम उसको कम देते हैं तो कर्जे से लदा होने के कारण देश की अर्थ व्यवस्था के ऊपर उसका बुरा असर पड़ता है। मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि आपको 1983 में चीनी और कपास दोनों का आयात करना पड़ेगा और इस कारण से देश की अर्थ व्यवस्था के ऊपर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। आपको चाहिए कि आप अपनी नीति को बदलें।

आज भी भारत के आधे से अधिक किसानों की पैदावार का जो एवरेज होता

[श्री चन्द्रजीत यादव]

है वह दुनिया में सब से कम है । एक पैरा मैं कोट करना चाहता हू । हमारे देश के जाने माने अर्थ शास्त्रियों भल्ला और अलघ ने अपने अध्ययन की बुनियाद पर कहा है :

"It should not be forgotten that even no almost half the area contributing nearly half the output in India is still in the average productivity category and as much as about one-third of the area producing nearly 1/6th of output still belongs to a very low category. Further more, high growth about 4.5 per cent is confined only to 17 per cent of the districts (10 per cent of area) and 25 per cent of the districts have actually recorded a negative growth rate."

इस साल आप 134 मिलियन पैदावार का अंदाजा लगाते हैं । लेकिन पिछले सालों को आप देखें । जिस साल पानी कम बरसा, सूखा हुआ हमारी पैदावार गिर गई । बुनियादी तौर पर आज भी हम प्रकृति के ऊपर निर्भर करते हैं । आप सिंचाई को बढ़ाए । बिजली का रेट बढ़ाने के बजाए उसको पूरी बिजली दें । उनकी जो ज़रुरतें हैं उनको पूरा करें । जिस तरह से — कारखानेदारों को उनका मुनाफ़ा लगाकर आप कीमत देते हैं दूसरी चीजों की कीमतों के साथ जोड़ कर उसकी कीमत देते हैं उसी तरह से आप किसान को भी दें । गांवों के विकास के ऊपर आप ज्यादा ध्यान दें । इससे देश में गरीबी की समस्या, विषमता की समस्या और गरीबों की समस्या भी हल होगी ।

जो कीमत आपने गेंहू की घोषित की है उसके ऊपर आप पुनर्विचार करें । आप दिल्ली के, हरियाणा के बाजारों में चले जाए । आज भी वहां 185–190 रुपये क्विंटल पर गेहूं बिक रहा है । आपने 142 रुपये कीमत घोषित की है । बाज़ार में जो दाम है उस हिसाब से कम से कम 180–185 रुपये तो आपको किसान को देने चाहिए ।

मैं आशा करता हूं कि कृषि मंत्री इन बातों पर ध्यान दे कर किसान विरोधी नीति को बदलेंगे और ऐसी नीति बनाएगे जिससे गांवों का और देश का कल्याण हो ।

SHRI RAJESH PILOT (Bharatpur): Sir, first of all, I want a decision from the Chair. All the time we hear shouts from the other side: "We are the kisans' sympathizers." During the debate on the kisans, Sir, please see how many from the other side are sitting; and how many we are sitting. Take the ratio. I want a decision from you. These people shout more for kisan; we do more for kisan.

Sir, much has been done for kisans; but more is required to be done.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Pilot, though they are not here, their hearts are always with kisans; you don't know.

SHRI RAJESH PILOT: The point is tht the Agriculture Prices Commission has not been touched. (*Interruptions*) I would request the hon. Minister to review the Agricultural Prices Commission's composition. I request the hon. Minister to restructure its composition. Some more formers should be inducted into it.

My last point is this whatever policy Government has made for farmers, is good. There is no doubt. But they have not been implemented. So, I would request the hon. Minister to have a monitoring cell, and to have a surprise squad check; and find out how far their policies are being implemented.

I will not take more time; I would just finish my speech with one request. The Government that is now in power knows better what is best for the farmers. But I only request that whatever policies they make should be implemented, and that there should be monitoring and feed-back, to say that such and such things have been done, and such and such things have not been done.

I would request the hon. Minister to assure the House that implementation of the policies will be 100 per cent. Thank you.

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT AND CIVIL SUPPLIES (RAO BIRENDRA SINGH): I am greatful to the hon. Members who have shown so much interest in the debate on the Demand of the Ministry of Agriculture and Rural Development. It will not be possible for me to reply to all the points that hon. Members have raised during this debate which has lasted for more than ten hours; but I shall try to clarify some of the misunderstandings and misapprehensions that the hon. Members are suffering from.

I am very happy that there has been a general appreciation in the House of the Government's efforts to specially improve the lot of the farmers and the rural masses, and to develop agriculture in this country on modern lines. This is an agricultural country. The Government of Mrs. Indira Gandhi knows very well that the backbone of the nation is the agricultural community. They are the most hard-working class. They supply the bravest of soldiers. It is these people who have sustained this nation over centuries. They are also honest. They are least given to corruption, evil designs and intrigues. They don't indulge in any blackmarketing. They don't indulge in hoarding. And it is the wish of this Government, as also expressed by all the speakers in the House, that the agriculturists, i.e. the farmers in this country need better attention, and should be given better attention. And what we have been able to do, not only during the last 15 or 16 years under the leadership of Mrs. Indira Gandhi, but also before that, under the leadership of the late Pandit Jawaharlal Nehru, has shown results. Agriculture has developed and developed fast. Irrigation has expanded in this country at a rate faster than known elsewhere in the world, from the potential of 22 million hectares that we had in 1950-51, this is not an insignificant achievement that now we can boast of having created a potential of nearly 60 million hectares under irrigation. Irrigation is the most important input for agriculture.

Next come seeds, seeds of good quality, high yielding variety. Then comes fertiliser, not only fertiliser-consumption but also fertiliser production. And the world knows that our fertiliser consumption from a level of only 69,000 tonnes in the year 1950-51 has jumped upto 60 lakh tonnes now. Production of fertiliser in this country was only 18,000 tonnes 30 years ago, when India became independent. Now, we are in a position to produce within this country about 40 lakh tonnes of fertiliser. This is on account of the attention that has been given to all these areas. Foodgrains production, according to some hon. Members who have criticised us, has not increased. If production has not increased, how is the nation being fed? Has not the population risen during the last so many years, from 35-36 crores to nearly 70 crores now? Who has been feeding this large population.

During the last 5 years, after 1976, practically no foodgrains were imported except what we imported recently, about 22 lakh tonnes; and that too because of the very bad drought that we experienced in 1979-80. Of course, this was on account of the large buffer stock that we were able to maintain; that we did not import any foodgrains from outside. Compare these condi-

[Rao Birendra Singh]

tions to the conditions during the Bengal famine. More than 40 lakh people perished on account of hunger. That was the femine only confined to a small part of the country. And this last drought affected more than 38 million hectares of land under crop; more than 220 million people were affected. Drinking water was not available. It had to be supplied to every person even if we had to use military trucks or railway trains. Food had to be dropped from air. But not a single man, not a single person in this country was allowed to die of hunger during that drought. Is this not an achievement of the Government of Mrs. Gandhi?

Foodgrains production is now being admired, so far as India's efforts are concerned, by the entire world, the world organisations, experts in agriculture. But some of our friends refuse to open their eyes. I do not know how to convince them that our figures are not figures on paper. This is a simple truth; this is a fact. Read FAO estimate of India's foodgrains production. They do not entirely depend upon our figures. They make their assessment also on the basis of available satellite studies and other information, their own way of finding out what is the position. It is estimated that with this year's crop which is coming to an end, we may be able to produce about 134 million tonnes of foodgrains, which is the record highest ever achieved by this country: and this is for a period during which agriculture suffered badly. We had achieved a production level of 132 million tonnes. But within one year it came down to about 109 million tonnes, a loss of nearly 23 million tonnes on account of bad weather conditions, scarcity of grains, drought, etc. But an hon. Member spoke about agriculture still being dependant on weather. Is there any country in the world where agriculture is not dependent on weather? Even if we irrigate the entire land and bring it under cultivation, we still have to depend on weather. We have had a bumper crop this time which is now being harvested, but in the last few weeks untimely rain and hailstorms have caused damage. Could we prevent this? Is there any science so far known to man which can control weather? But in spite of this damage we are still very hopeful that this will be an all-time record in agricultural production which the country has ever seen.

Sir, the performance of a Ministry or a Department is seen first by the utilisation of its Plan allocation, proper utilisation, showing results; and then the economy that it brings about in non-Plan expenditure. I give you some information about agriculture and the Agriculture Ministry which comprises the Department of Agriculture and Cooperation. The total Plan and non-Plan allocation for 1881-82 was somewhere around 1,843.25 crores. The Revised Estimates—(Plan and non-Plan) was Rs. 1,794.24 crores. During the current year we have put before the House demands for Rs. 1,908,07 crores for the Department of Agriculture and Cooperation. I am very happy to say that out of the Plan allocation last year out of the total allocation for Agriculture, we were able to spend 99.1 per cent of the Revised Estimates. This is a very high figure of utilisation of funds by any Ministry. If you want to know about the reduction in non-Plan expenditure, during the last year, we curtailed it by Rs. 34.59 crores; and that shows that the Agriculture Ministry has been paying attention not only to utilisation of its funds but also to trying to economise because we know that every penny that is meant for the good of the farmer and development of agriculture has to be properly utilised.

If hon. Members want to know about production there is nothing new, it has been stated time and again in the House, they themselves have been talking about it and our friends from this side have given them most of the information. But I might again refresh

the memories of friends on the other side by giving a few figures. Rice production this year is expected to be 54.4 million tonnes as against 53.2 million tonnes last year. These are all rough estimates because final and correct estimates are received after the close of agricultural year. Wheat production is expected to be 37.6 million tonnes as against 36.5 million tonnes last year. Cotton production has gone up from 7.6 million bales to 8 million bales. Potato production has gone up from 9.6 million tonnes to 10.6 million tonnes. You know how potato marketing is being looked after. This has been discussed in the House. Oilseeds is one crop which has received attention from almost every hon. Member, who has spoken on the Demands of the Agriculture Ministry. Its production has gone up from 9.4 million tonnes to 11.2 million tonnes. I do not claim that there is a major break through. But this side also is not neglected. We are spending money on research of oilseeds, and on pulses programme, apart from what the universities and the States are doing. The Indian Council of Agricultural Research alone has set a side about Rs. 15.6 crores on oilseeds research this year.

The development of agriculture can be judged by the consumption of inputs like fertilisers. The consumption of fertilisers has gone up by 11.1 per cent during this agricultural year as compared to the last year. It has now gone upto 61.3 lakh tonnes. High yielding varieties of seeds and the area under their cultivation also will show how improvements are taking place and what steps are being taken to increase the production. The area under high yielding varieties of seeds has gone up to 46.68 million hectares. There is a special programme for bringing larger areas under high yielding varieties.

Not only traditional crops in agriculture but forests also are receiving our attention specially. Everybody knows the interest of the Prime Minister in conservation and protection of forests. You will be glad to know that compared to about Rs. 30 crores spent on forestry during the last thirty years, the Sixth Plan provides Rs. 105 crores. Within this year, we have proposed an allocation of Rs. 22 crores. If you compare it with what has been spent in the last 30 years, you will know how much importance is being given to forestry. Some hon. Members have spoken about forests not receiving attention. I agree that there was large scale degradation of forests during the previous years. But we have been able to check this destruction. At the instance of the Prime Minister, this House enacted the Forest Conservation Act not very long ago. During the last 30 years the forest area was being reduced by about 1.5 lakh hectares every year and a total of more than 42 lakh hectares was diverted from forest to non-forest purposes. Now the House would be glad to know that we have come down to a figure of only about 3,000 hectares per year, which is still going out of the forests. Of course, we have brought it down from 1.5 lakh hectares to 3,000 hectares per year, but we want to stop it altogether.

Hon. Members already know, because we have informed the House several times, that we are working on a comprehensive Bill. Forest belongs to the States. We try to guide them and assist them. There are still areas where the Forest Act does not apply. We want to be more strict. At the same time, we want to safeguard the interests of the tribals, the people who earn their living out of forests. It is in the interests of the tribals themselves that the forests are preserved, that the area under forests increases and the forests are rejuvenated so that they could continue to live on the income from the forest produce.

My friend, Shri Baleshwar Ram, was to speak on the Demands of the Ministry of Rural Development. Un-

[Rao Birendra Singh]

fortunately, he could not get time, because hon. Members had priority, and they took most of the time. Some of the subjects have been dealt with by my colleague, Shri Swaminathan. I would not repeat the points he has already dealt with.

Rural development is as important as agriculture; it is part of agriculture. That is why these Ministries have been put under one charge. If the conditions of living of the poor people living in the villages, in the rural areas, do not improve, agriculture cannot be developed. This is why a big Ministry of Rural Development has been created by Shrimati Gandhi under the charge of a Cabinet Minister. The allocations for rural development are substantial. Hon. Members would have looked into the figures; I would not quote all those again. Still, I would like to mention some of the important figures. The plan allocation for integrated rural development is Rs. 1,500 crores. About 15 million families in 5 years, or three million families every year are to be brought above the poverty line.

I would not go to the extent of saying that poverty can be eliminated by these programmes, because poverty is a very big problem for India. About 45 million families in India are below the poverty line, in spite of the fact that the poverty limit in India has been put at a very low level. Any family that does not make Rs. 3,600 in a year is considered a poor family. With the present prices and the cost of living, I would not be able to say where the line should be. Compared to the other advanced countries, even the middle classes can be called poor, because they lack many of the amenities of life; comforts are out of the question. We are trying to attack poverty, which has been afflicting our rural masses for a very very long time. The amount of subsidy provided under this programme in anything from 25 per cent for small farmers to 33 per cent for marginal farmers and up to 5 per cent for tribals. The amount of subsidy available is ranging from Rs. 3000 to Rs. 5000. They can set up small units of poultry, piggery, sheep and goats, they can animals. i.e., piggery.

16 hrs.

Then we have a special livestock development programme which is also in close collaboration with the Integrated Rural Development Programme.

Another important programme is National Rural Employment Programme. The plan allocation under this programme is Rs. 1620 crores. Rs. 980 crores are in the Central sector. For this year alone we have demanded Rs. 190 crores in the Central sector like Rs. 180 crores that we have demanded for IRD. Everybody knows what impact this programme has created. though it is now on 50:50 basis, 50 per cent has to be matched by the States and 50 per cent is from the Government of India. This is a programme which is transforming the shape of rural India. Lanes and paths have been made pucca, Harijan bastis have been electrified, tubewells have been given more connections, school buildings have been repaired, seva kendras have been constructed and water supply schemes have been provided to the villages. Various programes in the villages are being implemented under this National Rural Employment Programme. About one million people are being employed every day in India under this programme. That is a small number, and we hape during the next year also the employment provided to the people will be from 350 million to 400 million mandays. Foodgrain is also being given. There is 40 per cent cash for purchase of material for creation of durable assets and 60 per cent is met from wages. It will not be correct to say that we have been able to provide employment to all villagers, but something has been done and I am glad that is being appreciated by the hon.

Members. Apart from this, we have several other programmes for rural areas like the DPAP (the Drought Prone Areas Programme) which is running in about 554 blocks in the country, and Rs. 15 lakhs....

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा): भीलवाड़ा में डी०पी०ए०पी० का प्रोग्राम नहीं चल रहा है। इसको वहां करवाइए।

राव वीरेन्द्र सिंह: वह भी करवायेंगे।

Rs. 15 lakhs are being given to each block for development purposes every year. Similarly under the Desert Development Programme Rs. 15 lakhs is given to each block. That is also going in more than 20 districts.

There have been some complaints as Mr. Vyas said. Some blocks which should have been covered under the DPAP have been left out. Some other blocks are getting double benefits. They are covered by DPAP as also by the Desert Development Programme. Sir, we are trying to look into the imbalance that has been created. We set up a task force, the task force has gone into the whole question of removing discrimination, wherever it has been noticed, the States will be consulted. We want all areas to have desired and deserved consideration and to be covered under this programme. I am afraid that some areas which have been unduly benefited may have to lose some benefits which they have undeservedly gained and enjoyed over the years during the past. I would not like to talk more on one subject alone.

There are various other programmes under the Ministry of Rural Development—warehousing programme for rural areas. 25 per cent subsidy is available from the Government of India. (*Interruptions*)

Setting up rural khaddi—khaddi village industry is under the Ministry of Industries. It is not under my Ministry.

2 milion tonnes of storage is to be created during the Sixth Plan. During 1982-83 5 lakh tonnes is intended to be created with an outlay of Rs. 3 crores.

Some hon. Members have talked about the land reform. The position has been explained time and again. We are trying that the surplus land should be distributed at the earliest so that the poor sections of the society, the landless people, the Scheduled Castes people, they get some share in the national asset, which is land.

We have demanded for assistance under the land reform programme a sum of Rs. 3.97 crores for this year—1982-83. I hope the hon. Members will agree that this is also a very important demand and there will be no objection to these welfare measures which the Government wants to take.

Rural roads are also receiving greater attention at our hands.

Foodgrains production would be 134 million tonnes. It was 130 million tonnes in the previous year. That should be clear to the hon. Members.

Hon. Members have shown concern all around for prices that the agriculturists are getting. I do not know what do they expect? But if they would believe a farmer who also feels for the farmers like themselves, I want to assure the hon. Members that Government is very keen to see that fair price is paid to the farmer a remunerative price. The wheat price that we have fixed at Rs. 142 for procurement, to my mind should satisfy the hon. Members. Because once....(*Interruptions*). So far as satisfaction is concerned farmers all over the world are the same. They can never be satisfied all over the country. I as a farmer, may not feel satisfied. But Government has its own limitations. I would like to inform the hon. Members and I would request them too to look into the past. Some years ago when there was another Government

[Rao Birendra Singh]

at the Centre, the rise in price from year to year for the major crop— for wheat the rise was only by less than 2.5 per cent. But since this Government has taken over, what we have done needs no beating of the drum.

Hon'ble Members know in their heart of hearts that wheat price has, from Rs. 117, gone up to Rs. 142 within two years.

SHRI CHANDRAJIT YADAV: By how much have the prices of fertilizers gone up?

RAO BIRENDRA SINGH: The fertiliser price has not risen much. In comparison to this, it is very negligible. It does not make a different of more than Rs. 2 to Rs. 4 per quintal in production cost. You can calculate that. I am satisfied. If you are not satisfied, you talk to me when you find time. (*Interruptions*) Everything was included. It is 9 to 10 per cent increase every year. Every year, 10 per cent increase roughly in wheat price and about 10 per cent increase every year in paddy price.

We have put up paddy price during the last two years from Rs. 95 to Rs. 115 per quintal. Coarse Kharif, cereals similarly, we have put up from Rs. 95 to Rs. 116 per quintal. See the jump. How liberal are we? And yet, you would not be satisfied because of politics. Groundnuts received a special attention. From Rs. 206 a year ago, the minimum support price of groundnut has been fixed at Rs. 270. A jump of Rs. 64 per quintal within one year. The support price of sun-flower seed has been raised from Rs. 183 per quintal to Rs. 250 per quintal. And yet can anybody say, farmers are not getting remunerative prices and the Government is not keen to give high prices to farmers? Soya-beans, from Rs. 183 a year ago, we have increased to Rs. 210 per quintal. This is to give a boost to the production of these crops. And yet, the hon. Members on the other side are not satisfied. I am confident that the farmers are satisfied. Therefore, they have not been able to carry any conviction with the farmers even though they tried their best to instigate the farmers in the past. (*Interruptions*)

There has been a talk about parity of prices between agricultural produce and industrial goods or manufactured goods.

I would give the figures. During the last 12 months, from March 1981 to March 1982, the wholesale price index of all commodities in India rose by 1.7 per cent. In the agricultural commodities, the wholesale price index rose by 6.3 per cent. See, how we are trying to maintain the parity or giving much more than what parity demanded.

श्री सुन्दर सिंह : ठीक है—ठीक है।

राव वीरेन्द्र सिंह : चौधरी साहब, तकलीफ़ तो नहीं है, मैं किसानों की बात कर रहा हूं ।

श्री सुन्दर सिंह : आपकी मौजूदगी में किसानों को कोई तकलीफ़ नहीं हो सकती ।

AN HON MEMBER: He is only appreciating.

RAO BIRENDRA SINGH: Now, I come to the wholesale price index for manufactured goods about which the hon. Members have an impression that their prices are rising much faster and higher than the price of agricultural goods. In the manufactured goods, the wholesale price index has come down during the last 12 months from March to March, by 1.9 per cent. It is minus 1.9 per cent, as compared to the price index of agricultural commodities which has risen by 6.3 per cent. That should satisfy the hon. Members that this Government is not only trying to maintain parity but is also trying to make up for the previous years.

There has been some mention of agricultural credit not being available in plenty or adequately to the farm sector. If this Government has done the most admirable thing for providing inputs to the farmer, the best has been done in the matter of supply of agricultural credit. In the year 1972-73, the total credit available to the farm sector both from cooperative and from all finincial institutions was Rs. 966 crores. In the year 1980-81 it went up to Rs. 3391 crores. By the end of this Plan period, in the year 1984-85, we hope to raise the farm credit availability to agriculture to Rs. 5,400 crores. We hope that there will be no dearth of credit for agriculturists.

Some hon. Members also talked about the report of the National Commission on Agriculture. The National Commission on Agriculture made in its report 2361 recommendations. The House will be glad to know that out of these 2361 recommendations, 1842 recommendations have been accepted by the Government and are being implemented. 166 more recommendations have been accepted and will be implemented. 328 recommendations are under examination. They need some further examination and we hope anything that is necessary for the welfare of agriculturists will be acceptable to Government. There are only 25 recommmendations out of these 2361 recommendations that have not been accepted. That is a very small number. They have been properly examined and it has not been found possible to accept them.

I would not like to reply to all the points made by all the hon. Members. But I would like to mention athrough reat Habour here made some of them very goon contribution. Gen. Sparrow is siting here. Mr. Bhim Singh is not there, but he spoke very well. Mr. R.L.P. Verma was only obsessed with the suicides of scientists. I do not know who feeds them with information and how they get it. It has been clarified in the House time and again that since 1960, there were 4 weaths amongst ICAR scientists and there are thousands on their roll. There was only 1 death which was established as a suicide because a suicide note was found. An inquiry committee with Dr. Gejendragadkar was set up and there were some recommendations made. Ever since this Government took over, we have looked into all the working and the rules and regulations of ICAR. We have streamlined the arministration. We look into all complaints and grievances speedily. I hope, the agricultural scientists would feel satisfied that they are getting due attention and respect at the hands of the Government. But sometimes it becomes very embarrassing for the Goverment when some of the scientists approach politicians. When we try to bring bad ones under discipline, then they approach my colleages here in Parliament, in the opposition and may be also on our side. I am sorry. Shri Dhandapani sitting there mentioned the case of an individual scientists, one Mr. Dhanaraj. He wanted his induction in Agricultural Research Service. His case was looked into and whatever was possible was done for him. But the case did merit consideration on the grounds that he had given for special consideration of a certain period during which he was on deputation to the Food Ministry being also taken into account for induction into Agricultural Research Service. But that could not be done as that was against the Rules. I hope you would agree that for Government employees or employees of an organisation under the Government to approach politicians to advance their personal interests is a wrong thing and must be discouraged..

SHRI M. RAM GOPAL REDDY: (Nizamabad): We approach them to find out their problems. Why do you think that they are approaching us?

RAO BIRENDRA SINGH: It is a matter of discipline and it is covered under the disciplinary rules.

SHRI C. T. DHANDAPANI (Pollachi): In the case of two other scientists

[Shri C. T. Dhandapani]

the Government has taken some other decision and they accepted even though they have not been qualified and they have been inducted. In that case these people approach us who have got a grievance.

SHRI RAO BIRENDRA SINGH: You are not doing any service to those friends for whom you are speaking. Anybody who raises the question of interest in service through a Member of Parliament is to be covered under the disciplinary rules and I would not think well of a scientist who comes that way asking for promotion or for certain benefits.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY: The Minister is also a Member of Parloament—I think.

SHRI RAO BIRENDRA SINGH: With a lot of hard work the agricultural scientists have given such a valuable help to agriculture in the country and their services are to be highly appreciated just as it is on account of the hard work of the farmers, because I have always maintained that it is the farmer's hard work which does more than anythingelse, for raising the production. The best compost for the land is the master's feet and hands. That is what I read sometime in schools in a poem.

Our agricultural scientists are also looking after areas in which they have not been very successful so far. Hundreds of crores of rupees are being spent on research in this country and we hope we shall be able to tackle all the problems. Seeds of many high-yielding varieties are being produced. Now we are paying special attention to production of adequate quantities of seeds as demanded by many hon. Members. They shoud be supplied to farmers according to their needs Universities are looking after it. It is not only the seed of food crops but also seedlings, good fruit trees and other trees of all varieties will be produced in huge quantities during the coming years and we hope we shall be able to overcome this shortage of seeds which was expressed by some hon. Members also by the farmers in the past.

Shri Virdhi Chander Jain, Choudhary Multan Singh and Mrs. Patnaik have given very good suggestions. Wherever we can look into those things and improve the functioning, we shall take all the steps. Shri R. L. Bhatia complained about Punjab farmers only being asked to supply foodgrains for our buffer stocks.

SHRI R. L. BHATIA: Punjab has been able to do the procurement. I am proud of Punjab as it gives fifty per cent of the total buffer stocks.

RAO BIRENDRA SINGH: I am also proud of the fact that Punjab has not given fifty per cent but it gives upto 70 per cent.

SHRI R. L. BHATIA: You must give them incentives.

AN HON. MEMEBERS: A fitting reply.

RAO BIRENDRA SINGH: On rice, Punjab and Haryana both gave over 70 per cent of the total procurement of the nation. (*Interruptions*) It does not mean that the country should not produce enough foodgrains for itself in certain parts and we should have to pay for the larger production in certain other States.

Even now, in our public distribution system, a subsidy of Rs. 40 per quintal is involved for the consumers in the distribution of wheat. There is a subsidy of Rs. 38 per quintal on distribution of rice. That is why we have been able to pay a higher price to the farmers on Punjab wheat. So is the case with regard to Haryana, U.P. and other States. As far as possible if they find any surplus, they procure from the market a very small quantity. We expect every State to do its bit. It can only procure where there is surplus. Can you imagine a situa-

tion where the F.C.I. does not enter the market in Punjab? You would have seen that last year we were late by five days in announcing the paddy price and so it came down to Rs. 90/-. And you were all shouting. If we stop the procurement of wheat and paddy in Punjab, you cannot imagine to what low level the price would go. This is how we are supporting the Punjab farmers. What more bonus do you want? If we do not undertake the procurement operations, where will Punjab farmers be? (*Interruptions*) We appreciate what is being done but, at the same time, Punjab is a part of the country. Punjab farmers get many other thing (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Singh, if you do not give them the bonus, at least you make a special mention of it here.

RAO BIRENDRA SINGH: Mr. Bhatia asked for licences for sugar mills. There are some applications pending from various States. Some States have been given a few licences for the sugar mills. Maharashtra has taken a lion's share because they know how to form cooperatives and how to send the applications in time. Now, we have a policy of equitable distribution of sugar factories in the country. Every State should come up and it should not be concentrated on one State alone. That is why we are goin a little slow. If one State is good in processing its applications and in sending them in time or before time, other States should also do the same thing. (*Interruptions*) The hon. Member is now speaking like Punjab. Why should you not produce more wheat and why sugar alone?

SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL (Kopargaon): Hhere there is discrimination in the levy sugar price.

RAO BIRENDRA SINGH: The sugar factories can transform the entire shape of the rural areas. Development should take place such as roads, electrification, schools, colleges, industries and everything. Therefore, everybody should have a fair share. I assure Mr. Bhatia that Punjab will also get its share licences for the sugar Mills (*Interruptions*) Mr. Tapeswar Singh said that Bihar should have licences for setting up sugar mills. But I would like to inform him that there is not a single application from Bihar for licence of the sugar mills. (*Interruption*) If there is no application at all how can we give a sugar mill licence? (*Interruption*) U. P. has got already, to my mind, 5 new factories licenced, they will thus have five new factories this year. (*Interruption*). You will get more; let others also get; there are many States which are not getting anything at all.

SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL: I asked about arrears of the cane-growers. Nobody is trying to lift the cane to the factory due to the poor price.

MR. DEPUTY-SPEAKER: We can't have a general discussion again. Please cooperate.

RAO BIRENDRA SINGH: Certain things which come from some hon. Members are such that I don't expect that they should be mentioned in the House. For instance one hon. Member mentioned the name of a chemical produce an international multinational company. That International and Multinational company produced something which they claimed would promote the growth of crop and all that. That has been tested. It has not so far been found that thatparticular chemical known as 'MIXTANOL if so effective as has been claimed by them. Now, it is Government's duty to see that anything that is produced here in the name of promoting growth of crops or protecting crops is a chemical which is really effective and that farmers are not cheated; because, they will purchase anything on account of the publicity that an international company can always afford. Therefore, it needs further testing. There has been no delay on the part of the

[Rao Birendra Singh]

ICAR. But hon. Members will appreciate that Certificate for effectiveness should be be given also hasity by a responsible organisation like the ICAR.

Sir, this is such a vast subject, I think I have already been hard on the House and on yourself, Sir, by taking too much time.

Rural Development and Agriculture find a very high priority in our 20 point programme. In the revised 20 point programme of the Prime Minister dry-land farming will receive particular attention. 15 million hectares of crop is sown in one State alone which produces only crop in the year. If a second crop could be grown there a lot more could be achieved. Similarly about oilseeds programme. Similarly, about pulses. They are all coming under this 20 point programme. Similarly bio-gas units. We are wanting to set them up. Now the new scheme of the Ministry of Agriculture provides for 100 per cent central assistance the States for subsidy. If States take initiative and set up bio-gas plants or gobar gas plants in villages, Goverment will help them. About forests, I have already dealt with....

SHRI M. RAM GOPAL REDDY: An important point is regarding the buffer stock of sugar and also late crushing. A lot of cane is wasted (*Interruptions*).

RAO BIRENDRA SINGH: We are aware of the fact that the factories have not been able to pay to the sugarcane growers on account of some restrictions on finance being provided by the banks at the same level as that of last year. But this matter has already been taken up by the hon. Finance Minister with RBI and I hope that enough finance will be provided, and sugar factories will be able to clear the arrears and these will not be allowed to be accumulated as far as our finances permit. Late crushing incentive also is under the examination of the Government. There has been some delay. But I will discuss the matter with my hon. colleague the Finance Minister, but, I may inform hon. Members that whenever the decision is announced, it will take effect from the previous time and so there need not be any anxiety on that score. The sugar factories will stand to gain even if it is announced late. On the same date, as it had been announced earlier, this will became effective.

श्री डिगम्बर सिंह (मथुरा) : लैंड एक्वीजीशन के बारे में नहीं बताया ।

RAO BIRENDRA SINGH: I wanted to say somthing on that point. But they diverted my attention. We have already promised that the Land Acquisition. Amendment Bill will be brought forward before this House. This has been mentioned to me by my colleague Mr. Bhishma Narain Singh. We want to keep our word to the House The Bill has not taken a final shape and I hope with the permission of the Chair, we shall able to trroduce it before the Parliament adjourns.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will ask the hon. Mnister whether he is prepared to clarify certain points raised by the hon. Members. All of you may please take your seats. Mr. Birendra Singh, are you prepared to clarify their points?

RAO BIRENDRA SINGH: I am prepared to clarify their points.

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि कृषि मूल्य आयोग ने अपनी सिफ रिश गेहूं के सम्बन्ध में 6 मास पहले भेज दी थी जिससे वोवाई से पहले मूल्य घोषित किया जा सके ? यदि हां तो अब तक इसे क्या इस कारण से रोका गया कि सरकार इस का मल्य कम करना चाहती थी या यह चाहती थी कि किसानो में पहले ही असंतोष व्याप्त हो जाय ?

दूसरे क्या कृषि मूल्य आयोग के एक सदस्य ने गेहूं का मूल्य 160 रुपये प्रति क्विंटल देने की सिफारिश की थी और कुछ

राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने 150 से 200 रुपये तक प्रति क्विंटल देने की सिफारिश की थी ?

RAO BIRENDRA SINGH: This point has already been mentioned that the recommendations from the various States differ. But we take an overall view and it takes time to process the recommendations of the Agricultural Prices Commission. We have to note the views of the States, wait for their comments and we also want to discuss the matter informally before we form our opinion. It makes no difference as to when the prices are announced, whether it is before the foodgrains are shown or before they start arriving in the market because till the last minute we want to see the trend and we also want to see if the prices of certain inputs have gone up even after the recommendations of the Agricultural Prices Commission. In the interest of the farmers, we wait and see till the end so that we can take into account the various conditiions prevailing.

श्री राम नगीना मिश्र (सलेमपुर) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । आज उत्तर प्रदेश की हालत यह है कि गन्ना खेतों में खड़ा हुआ है । किसान त्राहि त्राहि कर रहा है । उस को डर है कि उसका गन्ना खेतो में ही खड़ा रह जायगा और फ़ैक्ट्रियां उसे पेल नहीं पायेंगी । पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो हालत यह है कि गन्ना है तो कशर्स भी है और पूर्वांचल में केवल गन्नां है और फ़ैक्ट्रियां हैं । तो पूर्वांचल के लोग चिंतित है कि हमारा गन्ना खेतों में ही खड़ा रह जायेगा या पेला भी जायगा ? क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि एक भी गन्ना खेत में खड़ा नहीं रहने पाएगा ?

राव वीरेन्द्र सिंह : अब ऐसा आश्वासन मैं कैसे दे सकता हूं कि एक भी गन्ना खेत में नहीं रह जायेगा या कितना गन्ना खेत में रह जायेगा ।... (व्यवधान)...

Now, we are trying to see that there is the maximum crushing in the factories and for that purpose we are already thinking of providing late crushing incentive.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDAR (Durgapur): Sir, you know that the West Bengal Government has done a commendable job. Lakhs of share croppers have done a good work. But they are not getting loans from the banks. Previously, the Panchayats recommended the grant of loan to the share-croppers. Recently, the Finance Minister told the banks in West Bengal not to listen to the recommendations of Panchayats. Will you kindly contact the Finance Minister and see that the required action is taken?

Secondly, the Central Fisheries Corporation has been closed. In your chamber a meeting was held and you assured us that the employees of the Central Fisheries Corporation would be absorbed in other public sector undertakings, but nothing has been done so far ... (*Interruptions*).

RAO BIRENDRA SINGH: We are doing our best to see that as many employees of Central Fisheries Corporation possible are accommodated in other places in various Corporations, but all of them have not been accommodated so far. But as I have promised to the hon. Members in the House, we are trying our best. I am glad to hear that the West Bengal Government now has recognised the rights of bargadars and share-croppers. Ealirer they were reluctant to recognise them.

(*Interruptions*)

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां 15 हजार मजदूर जो कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं, उनको राहत कार्यों से

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

अलग कर दिया गया है । ऐसे लोगों को पुनः काम पर रखा जाना चाहिए ।

दूसरी बात यह है कि पिछला रिकार्ड देखा जाए तो जब भी राजस्थान में भयंकर अकाल पड़ा है तब दस लाख लोगों को काम पर लगाया जाता रहा है लेकिन इस साल केवल ढाई लाख लोगों को ही काम पर लगाया गया है । इसलिये आज जिन लोगों को रोजी रोटी की आवश्यकता है उनके लिये उसकी व्यवस्था दी जानी चाहिये ।

भीलवाड़ा जिले के लिये तीन कोआपरेटिव स्पिनिग मिल्स के लिये एप्लाई किया गया है। इसकी स्वीकृति ली जानी चाहिये ।

RAO BIRENDRA SINGH: I have taken note of what the hon. Member has said. We are aware of the drought conditions prevailing in Rajasthan. The Chief Minister has met me the other day. There has been a damage on account of hailstorm also in Rajasthan. Rajasthan has been getting maximum relief from Government of India and we are soon sending a Central Team to visit Rajasthan to see the conditions and we will do our best to help Rajasthan... (*Interruptions*).

SHRI C T DHANDAPANI: Only one uestion (*Interruptions*).

RAO BIRENDRA SINGH: You have already been given a chance. I will not reply to you now. I am not prepared to reply about individual scientist's matters.

SHRI C. T. DHANDAPANI: I am sorry, you have misunderstood me. That is not my question..(*Interruptions*).

SHRI ANANTHA RAMULU MALLU (Nagarkurnool): Many a time, the Andhra Pradesh Government has approached the Central Government to release an amount of nine crores under 'Food for Work' programme, which has been pending with the Government of India for quite some time past. The Government of Andhra Pradesh has made repeated representations for this. May I know whether the Government is considering to release that amount now?

In my parliamentary constituency, Kalva Kot taluk, is seriously affected with drought even this year also. I have submitted a representation to the Government of India as also to the Prime Minister that they should come to the rescue of the people, but no relief has been provided to the people so far .... (*Interruptions*).

Then, thousands of land reform cases are pending in the courts in Andhra Pradesh. Will the Government of India consider to advise the State Government to have special benches to dispose of these cases?.

RAO BIRENDRA SINGH: Rural Development Ministry is very prompt in releasing funds for all rural development schemes. And if any amount has been held up, it must be on Account of certain irregularities that have been noticed in the working of the State's Department. If a State Government makes use of our funds against the guidelines given by the Central Government, we have a right to look into the mal-practices that come to our notice. And we shall not release the funds to any State Government, unless they accept our guidelines. To my mind there was some complaint about the contractors having been employed for development work for which only the vil-

lagers were intended to be imployed. If that is the case, I am sorry, I cannot help the State Government.

MR. DEPUTY-SPEAKER I shall now put all the cut motions moved to the Demands for Grants relating to the Ministry of Agriculture to the vote together unless any hon. Member desires that any of his cut motions be put separately.

All the cut motions were put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put the Demands for Grants relating to the Ministry of Agriculture to vote.

The question is:

"That the respective sums not exceeding the amount of Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of India to *complete* the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1983, in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1 to 9 relating to the 'Ministry of Agriculture'."

The motion was adopted

MR. DEPUTY-SPEAKER: The Demands for Grants relating to the Ministry of Agricuture are passed.

Demands for Grants, 1982-83 in respect of the Ministry of Agriculture voted by Lok Sabha

No.of Demand	Name of Demand	Amount of Demand for Grant on account voted by the House on 16th March, 1982		Amount of Demand for Grant voted by the House	
1	2	3		4	
		Revenue Rs.	Capital Rs.	Revenue Rs.	Capital Rs.
MINISTRY OF AGRICULTURE					
1.	Department of Agriculture and Co-operation .	58,09,000	..	2,90,46,000	..
2.	Agriculture . .	15,10,10,000	198,78,64,000	75,50,51,000	993,93,18,000
3.	Fisheries . . .	2,98,12,000	1,38,95,000	14,90,61,000	6,94,74,000
4.	Animal Husbandry and Dairy Development .	22,71,22,000	1,35,17,000	113,56,10,000	6,75,88,000
5.	Forest . . .	6,06,33,000	12,50,000	30,31,66,000	62,50,000
6.	Co-operation . .	3,84,96,000	28,86,71,000	19,24,79,000	144,33,54,000
7.	Department of Food .	118,84,79,000	4,22,85,000	594,23,94,000	21,14,28,000
8.	Department of Agricultural Research and Education	13,47,000	..	67,36,000	..
9.	Payments to Indian Coouci nf Agricultural Research	18,86,37,000	..	94,31,83,000	..

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please don't record anything without my permission.

I shall now put all the cut motions moved to the Demands for Grants relating to the Ministry of Rural Development to vote together unless any hon. Member desires that any of his cut motions be put separately.

All the cut motions were put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put the Demand for Grant relating to the Ministry of Rural Development to the vote. The question is;

"That the respective sums not exceeding the amount on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of India to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1983, in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against Demand No. 75 relating to the 'Ministry of Rural Development'."

The Motion was adopted

MR. DEPUTY-SPEAKER: The Demand for Grant relating to the Ministry of Rural Development is passed.

Demand for Grant, 1982-83 in respect of the Ministry of Rural Development voted by Lok Sabha.

No.of Demand	Name of Demand	Amount of Demand for Grant on account voted by the House on 16th March, 1982		Amount for Demand for Grant to be submitted to the vote of the House	
1	2	3		4	
		Revenue Rs.	Capital Rs.	Revenue Rs.	Capital Rs.
MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT					
75.	Ministry of Rural Development . . .	75,03,82,000	8,20,000	375,19,11,000	41,00,000

DEMANDSx FOR GRANTS, 1982-83

Ministry of Communications

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, the House will take up the discussion and voting on Demands Nos. 14 to 18 relating to the Ministry of Communications for which six hours have been allotted.

Hon. Members present in the House whose cut motions to the Demands for Grants have been circulated may, if they desire to move their cut motions, send slips to the Table within 15 minutes indicating the serial numbers of the cut motions they would like to move.

A list showing the serial numbers of cut motions to be moved be put on the Notice Board shortly. In case any Members finds any discrepancy in the list, he may kindly bring it to the notice of the Officer at the Table without delay.

Now we start the discussion. Motion moved:

††Not recorded.

†Moved with the recommendation of the President.